



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222128  
CG-DL-E-29092020-222128

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]  
No. 270]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

मामला सं.- (एस एस आर) 07/2019

विषय – चीन जन. गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'स्टेनलैस स्टील - 304 ग्रेड का हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णयिक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/16/2019-डी जी टी आर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में भी संदर्भित) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में :

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात 'प्राधिकारी' के रूप में भी संदर्भित) ने दिनांक 11 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 14/30/2013 – डी जी ए डी के माध्यम से चीन जन. गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य (इसके पश्चात 'संबद्ध देशों' के रूप में भी संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'स्टेनलैस स्टील – 304 ग्रेड' के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों (इसके पश्चात 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पी यू सी' के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत की। उसके पश्चात प्राधिकारी ने चीन जन. गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए सिफारिश करते हुए दिनांक 09 मार्च, 2015 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/30/2013 – डी जी ए डी अधिसूचित किया। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 28/2015 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से पांच वर्षों के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. इस अधिनियम धारा 9क (5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क उस स्थिति में इस प्रकार के लगाये जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा, जब उसे पूर्व में रद्द न किया गया हो और प्राधिकारी से इस तथ्य की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या इस शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य के संबंध में घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करे कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

4. इस नियमावली के 23 (1ब) में निम्नानुसार प्रावधान है :

“... इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उस स्थिति में इसके लगाये जाने की तिथि से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं के पहल पर उस अवधि से पूर्व आरंभ की गई समीक्षा पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हों कि उक्त पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।”

5. मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमि. और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमि. (इसके पश्चात 'आवेदकों' अथवा 'घरेलू उद्योग' अथवा 'डी आई' के रूप में भी संदर्भित) ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आगोप लगाते हुए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक विधिवत प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किया और चीन जन. गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क अन्य पांच वर्षों के लिए जारी रखने तथा उसकी समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया है।

6. घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत की गई पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए और इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबद्ध में पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने की क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, की जांच करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. 7/16/2019 – डी जी टी आर के माध्यम से निर्णायिक समीक्षा जांच आरंभ की।

7. वर्तमान समीक्षा का क्षेत्र संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबद्ध में पूर्व में की गई जांच के सभी पहलुओं को शामिल करता है।

**ख. प्रक्रिया**

8. वर्तमान समीक्षा का क्षेत्र दिनांक 09 मार्च, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/30/2013 – डी जी ए डी जिसने चीन जन. गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध

वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने की सिफारिश की थी के सभी पहलुओं को शामिल करता है।

9. जैसा कि इसमें नीचे उल्लेख किया गया है, उस प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध निर्णयिक समीक्षा पाटनरोधी जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. 7/16/2019 – डी जी टी आर के माध्यम से सूचना प्रकाशित की।

ख. नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावास को जांच शुरूआत संबंधित अधिसूचना हेतु तथा आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति के साथ नियम 6(2) के अनुसार निर्णयिक समीक्षा जांच को आरंभ करने के बारे में सूचित किया गया था।

ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिसके नाम और पते इन आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे, को इस अधिसूचना की प्रतियां अधिसूचित की और इस नियमावली के नियम 6(2) और नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराने के लिए अवसर उपलब्ध कराया।

घ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ता संघों को आम नोटिस की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें सलाह दी कि वे इस पत्र के जारी होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत करायें।

ङ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना देने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं :

- (i) ताइयुवान आयरन एंड स्टील (ग्रुप) कं. लिमि. चीन. जन. गण.
- (ii) जियुक्यूअन आयरन एंड स्टील (ग्रुप) कं. लिमि. चीन. जन. गण.
- (iii) लियानजांग स्टेनलैस स्टील कोरपोरेशन, चीन जन. गण.
- (iv) बायोस्टील टॉवर, चीन जन. गण.
- (v) पोस्को, कोरिया जन. गण.
- (vi) बहरु स्टेनलैस एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

च. मैसर्स बहरु स्टेनलैस एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया जिन्होंने ध्वनि संबंधी अनुरोध दायर किये हैं को छोड़कर संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है और प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

छ. भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ संघों को इस नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना देने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं गई थीं :

- (i) रत्नामणि मेटेल्स एंड ट्यूब्स लिमि.
- (ii) संगीता मेटल (इंडिया), मुम्बई
- (iii) भंडारी फोयल्स एंड ट्यूब्स लिमि.
- (iv) रमणी स्टील हाउस
- (v) प्रकाश स्टीलेज लिमि.
- (vi) निशांत इनफिन प्रा. लिमि.
- (vii) राजेन्द्रा मेकेनिकल इंडस्ट्रीज लिमि.
- (viii) ए. सी. स्टील सोप, मुम्बई

(ix) फोनिक्स फोयल्स प्रा. लिमि.

(x) क्वालिटी फोयल्स (इंडिया) प्रा. लिमि.

(xi) डोमेट ट्रेडिंग प्रा. लिमि.

(xii) रेमि इडेलस्टल ट्यूबूलर लिमि.

(xiii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमि.

(xiv) वी आर वी एशिया पेसिफिक्स प्रा. लिमि.

(xv) हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमि.

(xvi) जे एन बी स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.

(xvii) रियल स्ट्रीप्स लिमि.

(xviii) यूनिस्टील कोरपोरेशन

(xix) श्री वेंकटेश वाँयर एंड स्टील्स प्रा. लिमि.

(xx) इनोक्स ट्यूब्स प्रा. लिमि.

(xxi) अपेक्स ट्यूब्स प्रा. लिमि.

(xxii) स्टील स्पेस प्रा. लिमि.

(xxiii) प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया

(xxiv) स्टेनलैस स्टील एक्सपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन

(xxv) ऑल इंडिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया

(xxvi) द तमिलनाडु स्टेनलैस स्टील मर्चेन्ट्स एंड मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन

ज. मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लिमि., मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लिमि., मैसर्स रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमि., मैसर्स क्वालिटी फोयल्स (इंडिया) प्रा. लिमि. ने वर्तमान जांच में आयातक/ प्रयोक्ता की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

झ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साध्य का अगोपनीय पाठ सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने सार्वजनिक फाइल से दस्तावेजों की प्रतियां और निरीक्षण का अनुरोध किया को उसे उपलब्ध करा दिया गया था। डी जी टी आर की वेबसाइट पर सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके लिखित अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को ई-मेल करने के लिए उसमें अनुरोध के साथ अपलोड किया गया था क्योंकि सार्वजनिक फाइल को चालू वैश्विक महामारी के कारण प्राप्त नहीं किया गया था।

ज. प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ उचित जांच के बाद गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे उस गोपनीय सूचना जिसे सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।

ट. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य से उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।

ठ. जांच 2015-16, 2016-17, 2017-18 की अवधि और जांच की अवधि को शामिल करते हुए क्षति के विश्लेषण के साथ अप्रैल 2018 – मार्च 2019 (12 महीने) (इसके पश्चात 'जांच की अवधि' अथवा 'पी ओ आई' के रूप में संदर्भित) की अवधि के लिए की गई थी।

ड. वाणिज्यिक सूचना एवं सांच्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि और जांच की अवधि की बाद की अवधि (अप्रैल 2019 – सितंबर 2019) के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था और डी जी सी आई एंड एस से ली गई उक्त सूचना को वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपनाया गया है।

ढ. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए इस नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेतू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच उस सीमा तक की है, जिस सीमा तक यह संभव हुआ।

ण. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित मौखिक सुनवाई जिसमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था, में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। मौखिक सुनवाई कोविड – 19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये थे, से अनुरोध किया गया था कि वे उसके पश्चात प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिए विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से इन दृष्टिकोणों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें।

त. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान जहां भी संगत पाया गया प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है।

थ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना दिये जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और इन अंतिम जांच परिणामों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किया है।

द. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 22 सितंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उसके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों जिसे प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया था का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, इन अंतिम जांच परिणामों में प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की जा रही है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है।

ध. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

न. जांच की अवधि के लिए विनियम दर प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए 1 यू एस डॉलर = 70.82 रुपए के रूप में लिया गया है।

ग. **विचाराधीन उत्पादन और समान वस्तु**

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “हॉट रोल्ड ओसटेनिक स्टेनलैस स्टील फ्लेट उत्पाद; चाहे वे आयाताकार रूप का फ्लेट, शीट अथवा क्वायल (हॉट रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड अथवा काला); या तो 304 अथवा 304एन अथवा 304एल अथवा 304एन अथवा 304एलएन अथवा इएन 1.4311, इएन 1.4301, इएन 1.4307 अथवा एक्स5सीआरएनआई1810 अथवा एक्स04सीआर19एनआई9 अथवा किसी अन्य मानकों जैसे यू एन एस, डी आई एन, जे आई एस, बी आई एस, ई एन, आदि के समतुल्य ग्रेड के; चाहे उत्कृष्ट अथवा काले फिनिश के साथ हो अथवा नहीं; चाहे वह उत्कृष्ट गुणवत्ता अथवा गौण हो या नहीं; चाहे मील एज अथरवा ट्रीम एज के साथ एज

की स्थिति वाला हो अथवा नहीं; क्वायल में 1.2 एमएम से 10.5 एमएम और प्लेट एवं शीट में 3 एमएम से 105 एमएम की मोटाई का; 1650 एमएम तक सभी चौड़ाई के (मिल ऐज के लिए 20 से अधिक एमएम और ट्रीम ऐज के लिए 5 से अधिक एमएम की चौड़ाई सहनशीलता)" है।

11. संबद्ध वस्तु सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 का प्रशुल्क शीर्षक 7219 और 7220 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।

**ग. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

12. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किया गया अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया अनुरोध निम्न अनुसार हैं :

क. उत्पाद का विवरण वही है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में निर्णय लिया गया था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण गणना क्रम नहीं हुआ है। इस कारण से याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में पूर्व में की गई जांच का उल्लेख करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं।

ख. प्राधिकारी ने मूल जांच में यह निर्धारण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आयात की गई सामग्री और उसके द्वारा उत्पादित वस्तु समान वस्तु है। आवेदक यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

**ग. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

14. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में होता है। मूल जांच में पी यू सी को नीचे दिये गये अनुसार परिभाषित किया गया था :

"हॉट रोल्ड ओस्टेनिक स्टेनलैस स्टील फ्लेट उत्पाद; चाहे वे आयाताकार रूप का प्लेट, शीट अथवा क्वायल (हॉट रोल्ड अनहिल्ड और पिकल्ड अथवा काला); या तो 304 अथवा 304एच अथवा 304एल अथवा 304एन अथवा 304एलएन अथवा इएन 1.4311, इएन 1.4301, इएन 1.4307 अथवा एक्स5सीआरएनआई1810 अथवा एक्स04सीआर19एनआई9 अथवा किसी अन्य मानकों जैसी यू एन एस, डी आई एन, जे आई एस, बी आई एस, ई एन, आदि के समतुल्य ग्रेड के; चाहे उत्कृष्ट अथवा काले फिनिश के साथ हो अथवा नहीं; चाहे वह वह उत्कृष्ट गुणवत्ता अथवा गौण हो या नहीं; चाहे मील ऐज अथवा ट्रीम ऐज के साथ ऐज की स्थिति वाला हो अथवा नहीं; क्वायल में 1.2 एमएम से 10.5 एमएम और प्लेट एवं शीट में 3 एमएम से 105 एमएम की मोटाई का; 1650 एमएम तक सभी चौड़ाई के (मिल ऐज के लिए 20 से अधिक एमएम और ट्रीम ऐज के लिए 5 से अधिक एमएम की चौड़ाई सहनशीलता)" है।

संबद्ध वस्तु सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय उप शीर्षक 7219 और 7220 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है।

15. "समान वस्तु" की परिभाषा से संबंधित इस नियम 2(घ) यह उल्लेख करता है कि "समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सदृश्य अथवा उसी के जैसा हर प्रकार से हो और इस प्रकार की वस्तु के न होने पर, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से एक जैसा नहीं हो, फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तुओं से बिलकुल मिलती जुलती विशेषताएं हों।

16. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद और भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये विचाराधीन उत्पाद की तुलना इन वस्तुओं की विशेषताओं, जैसे भौतिक और

रासायनिक विशेषताओं, कार्य और उपयोग, उत्पादन विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के संबद्ध में आयात किये गये संबद्ध उत्पाद से की जा सकती है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

17. इस प्रकार से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद इस नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

#### घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और उसकी स्थिति

##### घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. यह आवेदन जिंदल स्टेनलैस लिमि. और जिंदल स्टेनलैस (हिंसार) लिमि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन आवेदकों द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है। इसके अलावा, इन आवेदकों ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में किसी उत्पादक अथवा किसी आयातक से संबंधित हैं। इस प्रकार से, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक की स्थिति निर्णयक समीक्षा में आवश्यक नहीं है अतः आवेदक का यह अनुरोध है कि वे नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

##### घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

19. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है:

##### घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. इस नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है :

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाइत वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. वर्तमान निर्णयक समीक्षा आवेदन मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमि. और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिंसार) लिमि. द्वारा दायर किया गया है। इस देश में विचाराधीन उत्पाद के दो और उत्पादक अर्थात शाह एलायं और स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमि. हैं।

22. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों के पास भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में बहुत बड़ा अनुपात है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं और न ही संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबंधित हैं। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

23. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इन आवेदकों को इस नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानते हैं।

#### ङ गोपनीयता

##### ङ 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :

क. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर में बहुत अधिक खामियां हैं। किसी भी प्रयोक्ता ने उत्तर का अगोपनीय पाठ निर्धारित रूप में प्रस्तुत नहीं किया है और प्रस्तुत किये गये सभी उत्तर दिनांक 7 सितंबर, 2020 की व्यापार सूचना 10/2018 की पूर्ण उपेक्षा करते हुए दिया गया है। व्यापार सूचना के अनुसार प्रयोक्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे निर्धारित रूप में सूचना को प्रकट करें।

ख. इन प्रयोक्ताओं द्वारा उत्तर के अपने अगोपनीय पाठ में उपलब्ध कराई गई सूचना का घरेलू उद्योग के लिए कोई उपयोग नहीं है। पक्षकारों ने उत्तर में इस प्रकार की सूचना को प्रकट न करने के लिए समुचित कारण भी नहीं दिये हैं। न तो केवल इस सूचना को व्यापार नोटिस के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित हैं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना को भी इन पक्षकारों द्वारा गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।

ग. विगत में प्राधिकारी ने ब्राजील, इण्डोनेशिया और थाइलैण्ड से नाइट्रोसेल्यूलोज के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में इन निर्यातकों को उन सभी सूचना को प्रकट करने का निर्देश दिया था जिन्हें एन सी वी उत्तर में दिया जाना चाहिए था। वर्तमान मामले में प्राधिकारी को व्यापार नोटिस 10/2018 का पालन करते हुए उत्तर प्रस्तुत करने के लिए इन पक्षकारों को निर्देश देना चाहिए।

### **उ 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुबंध । में गोपनीय और अगोपनीय पाठ में सूचना को प्रकट करने के लिए दिशानिर्देश दिया गया है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के दो उत्पादक अर्थात मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमि. और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमि. हैं। व्यापार नोटिस के अनुबंध । में घरेलू उद्योग के कुछ विशिष्ट मानदंडों के संबंध में प्रकट का एक निश्चित मानदंड दिया गया है।

ख. व्यापार नोटिस सं. 10/2018 में 'क्षति रहित कीमत' के प्रकटन के लिए दिया गया मानदंड 'समग्र वास्तविक आंकड़े +/- 10 प्रतिशत की सीमा में वास्तविक आंकड़े अवश्य उपलब्ध कराये जाने चाहिए। उसका अनुपालन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है।

ग. व्यापार नोटिस सं. 10/2018 का उल्लंघन करते हुए, घरेलू उद्योग ने इस याचिका में अनेक प्रमुख अर्थिक मानदंडों को गोपनीय रखा है। इस प्रकार की सूचना के बिना, हितबद्ध पक्षकार आवेदक उद्योग के प्रतिसंबंधी मानदंडों की पूर्ण रूप से सार्थक जांच करने में सक्षम नहीं हैं।

घ. वास्तव में घरेलू उद्योग ने कुछ मानदंडों पर गोपनीयता का दावा करने के उद्देश्य से न तो सही कारण दिया है और न ही इस याचिका के तात्पर्य को सही तरीके से समझने के लिए उक्त मानदंडों के उचित अगोपनीय पाठ तथा डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यथाअपेक्षित इस याचिका की विषयवस्तु का समझने के लिए उचित अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

इ. आवेदक उद्योग द्वारा गोपनीयता का दावा निम्नलिखित कारकों के संबंध में बहुत अधिक है।

- दोनों याचिकर्ताओं की अलग अलग उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना (प्रवृत्तियों में)।
- प्रपत्र एल में सूचना।
- प्रपत्र एच में बिक्री से प्राप्त राशि।

च. यह अनुरोध किया गया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता के लिए दावे और न कि गोपनीय के रूप में बिना उचित जांच के निर्दिष्ट सूचना का मूल्यांकन करना चाहिए। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) इ. एल. टी. 673 (एस. सी.) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस संबंध में महत्वपूर्ण है। गोपनीय सूचना की विवेचना के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि गोपनीयता को स्वतः मंजूर नहीं किया जा सकता है और यह शुरू से अंत तक छानबीन के आधार पर होना चाहिए।

### **उ 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

26. इस नियमावली के नियम 7 में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

27. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 तथा नियम 6(7) के अनुसार सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच इस नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता संबंधी दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है।

#### च. विविध मुद्दे

##### च. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

##### च. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. प्राधिकारी ने पिछले 17 वर्षों में “स्टेनलैस स्टील का फ्लैट रोल्ड उत्पाद” के विभिन्न प्रकारों पर अनेक व्यापार उपचार जांच की हैं।

ख. जिंदल स्टेनलैस लिमि. सभी व्यापार उपचार जांचों में एकमात्र घरेलू उद्योग अथवा घरेलू उद्योग के विभिन्न घटकों में से एक रहा है। इस प्रकार से व्यापार उपचार उपायों की लंबी सूची के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को काफी लंबे समय से ग्रेड 304 सहित “स्टेनलैस स्टील का फ्लैट रोल्ड उत्पाद” के विभिन्न प्रकारों के आयात पर व्यापार उपचार उपायों के रूप में पर्याप्त संरक्षण मिला हुआ है। विशेष रूप से ‘304 ग्रेड के स्टेनलैस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों’ के आयातों पर घरेलू उद्योग को आगे संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग को “स्टेनलैस स्टील का फ्लैट रोल्ड उत्पादों” के विभिन्न प्रकारों के आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति का उपचार पहले ही व्यापार उपचार संबंधी उपायों के 17 वर्षों के दौरान किया गया है। इसके अलावा, इस याचिका में दी गई सूचना का विश्लेषण इसे स्पष्ट करता है कि घरेलू उद्योग को कोई ‘लगातार’ वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। घरेलू उद्योग को क्षति न होना इस तथ्य से भी देखा जाता है कि प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णायक समीक्षा की शुरुआत नहीं की गई थी अथवा जब यूरोपीय यूनियन, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताइपेई, यू.एस.ए से ग्रेड 304 का ए.एस.टी.एम का स्टेनलैस स्टील का

फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क दिनांक 24 नवंबर, 2016 को समाप्त हो गया तब निर्णायक समीक्षा को आरंभ किये जाने के लिए अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। अगस्त 2019 में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 'स्टील उत्पादों' पर रक्षोपाय शुल्क जांच आरंभ करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया है।

घ. सीमा प्रशुल्क 195 की धारा 9क(5) में यह उल्लेख है कि कोई भी लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 'ऐसे अधिरोपण की स्थिति से पांच वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी' हो जायेगा। इस नियम का अपवाद बहुत कठिन प्रयास से धारा 9क(5) के परंतुक में किया गया है जो केंद्र सरकार को उस स्थिति में पांच वर्ष की अवधि से आगे इन शुल्कों का समय विस्तार करने की अनुमति देता है। जब इसका यह मत हो कि 'ऐसे शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।'

ङ. यह स्पष्ट है कि विधायी आशय पांच वर्षों की अवधि तक शुल्क को लागू किये जाने को सीमित करना था। इस प्रकार ये शुल्क का समय विस्तार केवल अपवाद है और उसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। शुल्क को विस्तार करने के लिए, घरेलू उद्योग को प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए कठोर परीक्षा से गुजरना चाहिए कि इन शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/ फिर से होने की संभावना है।

### च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

31. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग को पिछले 17 वर्षों से व्यापार उपचार संरक्षण मिला हुआ है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर व्यापार उपचार उपाय 2015 से ही लगाया गया था। प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा जांच में इस तथ्य की जांच कर रहे हैं कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है या नहीं।

### छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

#### छ. 1. सामान्य मूल्य

32. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य यह है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
  - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
  - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।
 बशर्ते यह कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

#### छ. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के संबंध में किया जाना चाहिए। आवेदकों ने उचित लाभ

मार्जिन जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के लिए योग के बाद भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है, को शामिल करने के लिए समायोजित भारत में वास्तविक रूप से भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया है।

- ख. ऐसे इस स्टेनलैस स्टील समीक्षा प्रकाशन जो फ्लेट और लॉग उत्पाद के लिए घरेलू स्टील कीमत निर्धारण आंकड़ों को रिपोर्ट करता है के अनुसार प्रचलित कीमतों पर विचार कोरिया के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए किया गया है। इन कीमतों पर विचार सबसे अधिक बेची गई उत्पाद प्रकार की कीमत के रूप में किया गया है।
- ग. मलेशिया में सामान्य मूल्य के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ को जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित मलेशिया में उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है।
- घ. निर्यात कीमत की गणना के लिए, याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस से लिये गये लेनदेन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है और समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा खर्च, पोर्ट खर्च, बैंक प्रभार और अप्रतिदाय मूल्यवर्धित कर (केवल चीन के लिए) हेतु समायोजन किया गया है।
- ङ. संबद्ध देशों से आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक होना जारी है। इस प्रकार यद्यपि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है फिर भी वे पाटित कीमतों पर बाजार में आ रहे हैं।

#### छ. 3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

34. पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. बहरु ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि बहरु का जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का शून्य निर्यात हुआ है। किसी भी स्थिति में, संबद्ध वस्तुओं से संबंधित मूल जांच के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना था कि बहरु द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से 304 ग्रेड का स्टेनलैस स्टील का निर्माण संबद्ध वस्तुओं का “मलेशिया के उत्पादक” के रूप में अपने आपको न्यायोचित नहीं ठहराता है और अलग अलग व्यवहार बहरु को उनके पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए नहीं दिया जा सकता है।

#### छ. 4. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध करायें। हालांकि, संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है।

#### चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा

36. चीन के प्रवेश से संबंधित न्याचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

“गेट 1994 का अनुच्छेद VI, शुल्क और व्यापार पर सामान्य करार का अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में करार 1994 (“पाटनरोधी करार”) और एस सी एम करार निम्नलिखित के अनुरूप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य में चीन के प्रूल के आयातकों को शामिल करते हुए कार्यवाहियों में लागू रहेगा :

क) गेट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों या ऐसी पद्धति जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों से सही तुलना पर आधारित नहीं हो, का उपयोग करेंगे :

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में मौजूद हो, तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांच के अधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे।

(ii) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य ऐसी कार्यपद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों से सही तुलना पर आधारित न हो यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में तमाम उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

(ब) जैसे ही चीन ने आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह सिद्ध किया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उप अनुच्छेद (क) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जायेगा बर्तेरे कि प्रवेश की तिथि का आयात करने वाला सदस्य हो। किसी भी स्थिति में उप अनुच्छेद (क) (ii) के प्रावधान प्रवेश की तिथि के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जायेंगे। इसके अलावा, यदि चीन आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह सिद्ध करता हो कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित स्थितियां मौजूद हैं, उप अनुच्छेद (क) का गैर बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर अब लागू नहीं होंगे”

37. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के पाठनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किये जाने के लिए भारत के नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है।

#### **छ. 4.1 चीन जन. गण. से सामान्य मूल्य का निर्धारण**

38. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में निहित अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड पर पर्याप्त सूचना न रहने पर प्राधिकारी ने 'कोई अन्य उचित आधार' पर इस पद्धति पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

39. इस कारण से प्राधिकारी ने उचित लाभों के योग और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य तय किया है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाठन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **छ. 4.2 चीन जन. गण. से निर्यात कीमत का निर्धारण**

40. चीन जन. गण. के किसी उत्पादक द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, अप्रतिदाय मूल्यवर्धित कर, पोर्ट खर्च और अंतर्रेशीय भाड़ा शुल्क के आधार पर उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेनदेन वार जी सी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, चीन जन. गण. से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे दी गई पाठन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### **छ. 4.3 कोरिया गणराज्य से सामान्य मूल्य का निर्धारण**

41. कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाठन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### छ. 4.4 कोरिया गणराज्य से निर्यात कीमत का निर्धारण

42. कोरिया गणराज्य के किसी उत्पादक द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पोर्ट खर्च और अंतर्देशीय भाड़ा शुल्क के आधार पर उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेनदेन वार जी सी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, कोरिया गणराज्य से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### छ. 4.5 मलेशिया से सामान्य मूल्य का निर्धारण

43. मलेशिया के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्धारित रूप में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। बहरु स्टेनलैस एसडीएन. बीएचडी. ने केवल क्षति संबंधी अनुरोध प्रस्तुत किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### छ. 4.6 मलेशिया से निर्यात कीमत का निर्धारण

44. मलेशिया के किसी उत्पादक द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पोर्ट खर्च और अंतर्देशीय भाड़ा शुल्क के आधार पर उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेनदेन वार जी सी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, मलेशिया से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### छ. 5. पाटन मार्जिन

45. उपरोक्त में यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है।

#### पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यू.एस डॉलर/ मी.ट.)	निर्यात कीमत (यू.एस डॉलर/ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (यू.एस डॉलर/ मी.ट.)	पाटन मार्जिन %	डी.एम.रेंज %
1.	चीन जन. गण.	कोई भी	***	***	***	***	20-30
2.	कोरिया गणराज्य	कोई भी	***	***	***	***	10-20
3.	मलेशिया	कोई भी	***	***	***	***	0-10

#### ज. क्षति का आकलन, कारणात्मक संबंध पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

46. अनुबंध-II के साथ पठित इस नियमावली नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की

तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

47. इस नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान किसी समीक्षा की स्थिति में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो इस नियमावली के नियम 11 और अनुबंध ॥ के अंतर्गत अपेक्षित है और इस तथ्य की भी जांच की है कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

48. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के लिए आवेदन मैसर्स जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमि. और मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लिमि. द्वारा दायर किया गया है। इस नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में, आवेदकों को इस जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। इस कारण से, आवेदक जो नियम 2(ख) में यथापरिभाषित घरेलू उद्योग हैं, की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

### ज. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

49. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। हालांकि, इन आयातों का पाटित कीमतों पर किया जाना जारी है। अन्य देशों से आयातों में पाटित और सब्सिडीयुक्त कीमतों पर काफी हद तक वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और वास्तव में वह कीमत घरेलू उद्योग की विक्री की लागत से भी कम है। इस प्रकार से आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, विक्री और क्षमता का उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर पूर्व लाभ तथा निवेशों पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में जांच की अवधि में गिरावट आई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग एक बार फिर क्षति उठा रहा है। जबकि यह अधिकांशतः अन्य देशों में पाटन को परिवर्तित किये जाने के कारण हुआ है, यह स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में क्षति की संभावना और घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति को सिद्ध करता है।

ख. आयात पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर बहुत अधिक हुआ है। इसके अलावा आयातों में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

घ. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सबसे पहले सुधार हुआ और फिर उसमें लाभ, निवेश पर लाभ, नकद प्रभाव के संबंध में गिरावट आई और यह अन्य स्रोतों से पाटित और सब्सिडीयुक्त आयातों को देखते हुए एक बार फिर नकारात्मक स्तरों पर पहुंच गया है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग कमजोर स्थिति में है।

ङ. कारणात्मक संबंध को पहले ही मूल जांच में सिद्ध किया गया है। वर्तमान समीक्षा जांच में प्राधिकारी को विश्व व्यापार संघटन के करार के अनुच्छेद 11.3 के अनुसार केवल इस तथ्य की जांच करनी है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा फिर से होगी। इस प्रकार से, प्राधिकारी को पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने अथवा उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

च. अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में काफी हद तक वृद्धि हुई है और प्राधिकारी द्वारा ऐसे आयातों पर एक पृथक पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी जांच की जा रही है।

छ. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कमी नहीं आई है। इस कारण से मांग में संकुचन एक संभावित कारण नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में सहायक हो सकता था।

ज. विचाराधीन उत्पादक के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

झ. ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

ज. इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही आने वाले भविष्य में किसी परिवर्तन की कोई संभावना है। इस कारण से प्रौद्योगिकी का विकास क्षति का एक कारक नहीं है।

ट. आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात यथासंभव किया है। हालांकि, केवल घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना पर विचार क्षति के आकलन के लिए किया गया है।

## ज. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :

क. पाठनरोधी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध ।। के अनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण में पाठित आयातों के सकारात्मक साक्ष्य और वस्तुपरक जांच तथा ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव सामने है। हालांकि, वर्तमान जांच में, याचिकाकर्ता यह दर्शने में सक्षम नहीं हो पाये हैं कि घरेलू उद्योग को कोई पाठन अथवा परिणामी क्षति हुई है।

ख. याचिकाकर्ता यह दर्शने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पाया है कि संबद्ध वस्तुओं के क्षतित पाठित आयातों के कारण इस मामले में कोई वास्तविक क्षति हुई है अथवा क्षति के होने की संभावना है।

ग. प्राधिकारी को निम्नलिखित का निर्धारण अवश्य करना चाहिए :

- पाठित आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर पाठित आयातों का प्रभाव तथा कीमत ह्रास और न्यूनीकरण।
- बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार का हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता के उपयोग में गिरावट का मूल्यांकन।
- नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव।

घ. यह अनुरोध किया जाता है कि कीमत में कटौती संबद्ध देशों के लिए घरेलू उद्योग के अपने स्वीकारोक्ति के अनुसार नकारात्मक है। कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण के संबंध में, घरेलू उद्योग ने इस याचिका में स्वयं यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को अन्य स्त्रोतों से आयातों के कारण कोई कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण हुआ है।

ङ. इस आवेदन में क्षति का मार्जिन अथवा कम कीमत पर बिक्री की कोई जांच नहीं हुई है। इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात क्षतिकारक कीमतों पर हुए हैं।

च. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इस कारण से, संबद्ध देशों के निर्यातक भारत में प्रचलित कीमतों का मुकाबला कर रहे हैं जिसे घरेलू उद्योग तथा गैर संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।

छ. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अनुरोध घरेलू उद्योग की अपनी याचिका में जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण नहीं हुआ है, के प्रतिकूल है। इसके अलावा, यह अनुरोध रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल भी है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच मूल्य से कम है जो दर्शाता है कि वास्तव में घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों पर दबाव बना रहा है।

ज. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित एफ टी ए के कारण आयात सस्ती कीमतों पर हो रहे हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग का उक्त अनुरोध इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो संबद्ध वस्तुओं के पाठन को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुआ है।

झ. घरेलू उद्योग को हो रही कोई क्षति कथित पाठित आयातों को छोड़कर इन कारकों के कारण हुई है। वास्तव में घरेलू उद्योग की याचिका स्वयं विभिन्न स्थानों पर यह स्वीकार करती है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति कम कीमतों पर गैर संबद्ध देशों से आयातों की अधिक मात्रा के कारण हुआ है।

ज. जबकि संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की जांच की समग्र अवधि के दौरान काफी हृद तक गिरावट आई है, गैर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में काफी हृद तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से आयात कीमतों तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध देशों से इन कीमतों की तुलना में कमतर है।

ट. मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों को भारत में आयात के समय अधिमान्य सीमा शुल्क का लाभ नहीं मिलता है। यदि सीमा शुल्क मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर संग्रहित किया गया है तब प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण के लिए मलेशिया से आयातों के पहुंच मूल्य की गणना करते समय 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क को शामिल करें।

ठ. मलेशिया से आयात 3 प्रतिशत से कम है और उसे कोरिया गणराज्य तथा चीन जन. गण. से आयातों के साथ एकत्रित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी को मलेशिया से कथित पाठित आयातों के कारण क्षति के आकलन से कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. से कथित पाठित आयातों के संबंध में पृथक रूप से क्षति का आकलन करना ही चाहिए।

ड. मलेशिया से आयात वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में भारत में कुल आयातों का क्रमशः 0.05 प्रतिशत, 0.07 प्रतिशत, 0.18 प्रतिशत और 0.35 प्रतिशत था।

ढ. कुल मिलाकर, संबद्ध देशों से आयातों में पूर्ण मात्रा में 2015-16 में 26,062 मी. ट. से जांच की अवधि के दौरान मात्र 2,387 मी. ट. तक गिरावट आई, जो मूल मात्राओं के लगभग दसवें हिस्से तक गिरावट है।

ण. सापेक्ष रूप में भी, संबद्ध देशों से आयातों में कुल भारतीय उत्पादन और कुल भारतीय खपत की तुलना में गिरावट आई और यह 2015-16 में 100 सूचकांकों से जांच की अवधि में क्रमशः मात्र 7 सूचकांकों और 9 सूचकांकों तक गिरावट है।

त. यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि मलेशिया से आयात जांच की पूरी अवधि और क्षति की पूरी अवधि के दौरान हमेशा कम रही है। मूल में भी मलेशिया से आयात बहुत कम स्तर पर था।

थ. यह स्पष्ट है कि मलेशिया हमेशा पिछ्ले 10 वर्षों अथवा उसके करीब समयावधि में भारत को एक मार्जिनल (लगभग नगण्य) निर्यातक रहा है। इस प्रकार से, ऐसा कोई दावा नहीं हो सकता है कि मलेशिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

द. आयातों के कारण जांच की अवधि में कीमतों में कटौती नहीं हो रही है और कीमत में कटौती नकारात्मक है।

ध. कीमत मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का आकलन पूर्ण असावधानी से किया हुआ है और इसमें विशेष रूप से संबद्ध देशों से कीमतों के बारे में वैश्विक और घरेलू बाजारों में कीमत के उतार चढ़ाव का गहरी समझ का अभाव है।

न. यह अनुरोध किया जाता है कि सभी तीन संबद्ध देशों अर्थात् चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और मलेशिया से कीमत में कटौती 0.(10) की सीमा में है जिसका अर्थ यह है कि संबद्ध स्रोतों से कीमतें अपेक्षाकृत अधिक थीं और इसके कारण घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हुई। हालांकि, घरेलू उद्योग के पक्ष

में मानदंडों को तोड़ने मरोड़ने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग ने कुछ लेन देन को बाहर किये जाने का सुझाव दिया और शेष लेन देन के आधार पर कीमत में कटौती तय की।

प. मलेशिया से लेन देन के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने केवल हॉट रोल्ड फ्लेट प्रॉडक्ट प्लेट 304 से संबंधित सभी लेन देन को बाहर रखा है। उत्पादों की एक श्रेणी को केवल इस कारण से पूर्ण रूप से बाहर किया गया है कि इन उत्पादों का कीमत निर्धारण बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग कीमत में कटौती के लिए एक मामला जहां कोई भी मामला नहीं है बनाने का प्रयास कर रहा है।

फ. यह अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के द्वारा घरेलू कीमतों की कीमत में कटौती का आकलन करने में, प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्कों को जोड़ने के बाद आयात की कीमतों की तुलना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ग्राहक अपने आपूर्तिकर्ता के बारे में निर्णय लेते समय अपने द्वारा भुगतान योग्य अंतिम कीमतों की तुलना करेंगे और इस कारण से कीमत में कटौती को पाटनरोधी शुल्कों को जोड़ने के बाद आयात कीमतों के स्तर पर देखा जाना चाहिए। यह प्राधिकारी का विभिन्न मामलों दृष्टिकोण भी रहा है जहां कीमत में कटौती पर विचार ऐसे आकलन के उद्देश्य से आयात कीमतों में पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद किया गया था।

ब. यह अनुरोध किया जाता है कि जैसे ही पाटनरोधी शुल्क को मलेशिया से पहुंच मूल्य में जोड़ा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कीमत स्तर सभी अन्य स्रोतों से तुलनीय संबद्ध वस्तुओं की कीमत के स्तरों से काफी हद तक अधिक है और इन याचिकाकर्ताओं की एन आई पी की तुलना में भी तुलनीय/ अधिक है।

भ. मलेशिया से पहुंच कीमतों में क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि वृद्धि हुई है और वह जांच की अवधि के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर है।

म. मलेशिया से कीमत में कटौती (अनुमानतः बिना पाटनरोधी शुल्क के) नकारात्मक है, अर्थात मलेशिया से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की एन एस आर से अधिक था।

य. समग्र रूप में संबद्ध देशों से पहुंच कीमतों में क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि वृद्धि हुई है और वह जांच की अवधि के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर है।

कक. समग्र रूप में संबद्ध देशों से कीमत में कटौती (अनुमानतः बिना पाटनरोधी शुल्क के) नकारात्मक है, अर्थात समग्र रूप में संबद्ध देशों से पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की एन एस आर से अधिक रही।

खख. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में क्षति की अवधि और जांच की अवधि में सतत रूप से वृद्धि हुई है।

गग. जब वर्तमान मामले में पहुंच कीमतों में पाटनरोधी शुल्क कारक को शामिल किये बिना भी कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है तब संबद्ध आयातों की कीमतें स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में काफी हद तक अधिक है। ऐसे मामले में, संबद्ध देशों से आयातों का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है जिसके कारण कीमत पर दबाव पड़ता हो अथवा कीमत ह्रास या न्यूनीकरण हो रहा हो। जैसा कि वर्तमान मामले में तर्क दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये आयात भारत में ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी कीमतों पर नहीं हो रहा है।

घघ. कम कीमत पर बिक्री संबद्ध आयातों के कीमत के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मानदंड नहीं है। निरमा बनाम संघ सरकार में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने इस स्थिति को स्पष्ट किया है।

ड.ड. ऐसा प्रतीत होता है कि संरचित एन आई पी इन याचिकाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही वास्तविक स्थिति पर विचार किये बिना क्षति मार्जिन प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है।

चच. क्षति मार्जिन/ कम कीमत पर बिक्री के उद्देश्य से, प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के साथ पहुंच कीमत पर विचार करते हैं और इस प्रकार से निकाली गई कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की संरचित एन आई पी के विरुद्ध करते हैं।

छछ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपनी संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं की है।

जज. संबद्ध वस्तुओं के याचिकाकर्ता के उत्पादन में 2015-16 में 100 सूचकांकों से जांच की अवधि में 124 सूचकांक तक वृद्धि हुई है।

झझ. याचिकाकर्ताओं ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान अपनी क्षमता उपयोगिता में सुधार किया है और यह 2015-16 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 126 तक सूचकांक तक पहुंच गया।

ज.ज. याचिकाकर्ताओं ने क्षति के अवधि के दौरान पी यू सी के बढ़े हुए उत्पादन के समानुपात में पी यू सी की घरेलू बिक्री में वृद्धि की है।

टट. याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री पी यू सी के उत्पादन में सुधार के समानांतर 2015-16 में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 125 सूचकांक हो गया है।

ठठ. याचिकाकर्ताओं की उत्पादकता ने क्षति की अवधि के दौरान 100 सूचकांक प्रतिदिन से 127 सूचकांक प्रतिदिन तक सुधार दर्शाया है। प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि बेहतर उत्पादन को दर्शाता है जिसे बेहतर बिक्री और कमतर मालसूची के संदर्भ में अवश्य देखा जाना चाहिए।

डड. इन याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित माल सूची में काफी हृद तक गिरावट आई है अर्थात् यह 100 सूचकांक से घटकर 68 सूचकांक पर चला गया है।

ढढ. उत्पादन और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची 100 सूचकांक से लगभग आधा, 54 सूचकांक तक अग्रानुक्रम में गिर गया है।

णण. चूंकि क्षति रहित कीमत की गणना कारखानागत स्तर पर की जानी है, अतः स्टॉकयार्ड खर्च, विज्ञापन और प्रचार, बिक्री खर्च, भाड़े और फॉरवर्डिंग खर्च, संदिग्ध ऋण/ अग्रिम राशि, डूबा हुआ ऋण आदि के लिए प्रावधान जैसे निर्माण के बाद के खर्चों पर विचार क्षति रहित कीमत का आकलन करते समय नहीं किया जायेगा।

तत. इस तथ्य का भी सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए कि क्या जिंदल स्टेनलैस लिमि. का अनुसंधान और विकास खर्च पी यू सी से संबंधित है अथवा नहीं।

थथ. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में दिये गये आंकड़े/ सूचना में कमियां हैं। घरेलू बिक्री की पी बी आई टी प्रति इकाई जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक अर्थात् (206) सूचकांक है जबकि घरेलू बिक्री का कुल पी बी आई टी भी उसी अवधि के दौरान 27 सूचकांक है। नियोजित पूँजी के प्रतिशत के रूप में पी बी आई टी भी उसी अवधि के दौरान सकारात्मक है। यह अनुरोध किया जाता है कि यह किस प्रकार से संभव है कि जब घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदत्ता सकारात्मक है लेकिन घरेलू बिक्री की प्रति इकाई लाभप्रदत्ता नकारात्मक है। यह अनुरोध किया जाता है घरेलू उद्योग के आंकड़ों में खामियां हैं और इसे प्राधिकारी द्वारा शुरू से अंत तक जांच किये जाने की आवश्यकता है।

दद. याचिकाकर्ताओं ने या तो घरेलू उत्पादकों अथवा संबद्ध आयातों की कीमतों के विरुद्ध ऐसे आयातों की बिना किसी स्पष्ट कीमत तुलना के गैर संबद्ध स्रोतों से आयातों की बहुत अधिक मात्रा को नोट किया है। हालांकि, हम नोट करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि गैर-संबद्ध स्रोतों – विशेष रूप से इण्डोनेशिया और ताइवान से आयातों की बहुत अधिक मात्रा के कारण याचिकाकर्ताओं को क्षति, यदि कोई हो, हो रही है।

धध. इण्डोनेशिया और ताइवान से आयातों की मात्रा संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा से काफी हृद तक अधिक है। वास्तव में, इण्डोनेशिया और ताइवान से आयात गैर संबद्ध आयातों का लगभग 90 प्रतिशत है।

नन. जबकि संबद्ध देशों से आयात समग्र गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है, इण्डोनेशिया और ताइवान से आयातों में पिछले दो वर्षों में अचानक वृद्धि हुई है और यह भारत में आयातों के 85 प्रतिशत के साथ भारत में कुल आयातों का बहुत अधिक बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया है।

पप. इण्डोनेशिया और ताइवान से आयातों की बहुत अधिक मात्राओं के साथ साथ – वे कीमत जिन पर ऐसे आयात भारतीय बाजार में आ रहे हैं, भी काफी हद तक कम है और तुलनात्मक रूप से मलेशिया से कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं।

फफ. चीन जन. गण., ताइवान, इण्डोनेशिया, यू.एस.ए., थाइलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, हॉगकॉंग, वियतनाम और मलेशिया से स्टेनलैस स्टील के फ्लेट उत्पादों के कारण एक समानांतर जांच चल रही है। प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोहरे उपचार की कोई स्थिति नहीं है अथवा यह कि संबद्ध देशों को गैर संबद्ध देशों द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए अनुचित रूप से दण्डित नहीं किया जाये, वर्तमान जांच में कार्रवाई करने के पूर्व उस जांच में क्षति का आकलन अवश्य करना चाहिए।

बब. याचिकाकर्ता की लाभप्रदता और उस पर प्रभाव की आसानी से व्याख्या की जाती है जब उसे इण्डोनेशिया और ताइवान से आयातों के संदर्भ में देखा जाये।

भभ. इण्डोनेशिया और ताइवान से अचानक वृद्धि घरेलू उद्योग की स्थिति में टर्न अराउण अर्थात अत्यधिक लाभ से 2017-18 और 2018-19 (जांच की अवधि) के वर्षों में आश्चर्यजनक हानि के समय हुई है। इसके पहले, ताइवान से आयात की मात्रा अपेक्षाकृत और इण्डोनेशिया से आयात की मात्रा शून्य थी।

मम. एक ओर संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और उनकी कीमतों की तुलना याचिकाकर्ता की विक्री की लागत से की गई और वहीं दूसरी ओर विक्री कीमत और लाभप्रदता कोई प्रवृत्ति अथवा सह-संबंध को नहीं दर्शाता है। बल्कि यह अस्पष्ट तस्वीर दर्शाती है जिसमें याचिकाकर्ता की कीमतें उस समय कम की जा रही हैं जब संबद्ध आयातों की कीमतें बढ़ रही हैं।

यय. इण्डोनेशिया और ताइवान से कम कीमतों पर बढ़ता हुआ आयात 2017-18 में भारत में आना शुरू हुआ और उसी समय याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता के मानदंडों में पूर्ण रूप से गिरावट आई। समवर्ती से, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की मात्रा और कीमत को भी देखा जा सकता है – मात्रा नगण्य है और कीमतें तुलनीय स्तर पर हैं। मलेशिया के संबंध में, मलेशिया की कीमतें 2017-18 और जांच की अवधि के दौरान इण्डोनेशिया और ताइवान की कीमतों से बहुत अधिक हद तक अधिक हैं।

### **ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

51. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

52. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में यह प्रावधान है कि किसी समीक्षा के मामले में भी रूल 11 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इस कारण से प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण किया है। अनुबंध-II के साथ पठित इस नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए . . .” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या

इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास होता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

53. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, इस नियमावली के अनुबंध-॥ के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

54. वर्तमान क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदत्ता पर इसके प्रभाव की जांच पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो तथा क्षति के मौजूद रहने की जांच करने के लिए की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार किया है और इस नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है।

55. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड बदतर स्थिति को दर्शाते हों। कुछ मानदंड बदतर स्थिति को दर्शा सकते हैं जबकि कुछ अन्य मानदंड बदतर स्थिति को नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है।

### I. मांग का आकलन

56. इस उद्देश्य से, भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में लिया जाता है। भारत में मांग/ खपत में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
<b>आयात की मात्रा</b>					
चीन जन. गण.	मी. ट.	24,256	7,152	6,558	564
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	29	27	2
कोरिया गणराज्य	मी. ट.	1,782	942	1,852	1,633
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	104	92
मलेशिया	मी. ट.	24	21	85	191
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	362	811
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. ट.	26,062	8,115	8,495	2,387
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	33	9
अन्य देश	मी. ट.	18,264	21,457	38,287	52,893
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	210	290
कुल आयात	मी. ट.	44,326	29,573	46,782	55,280
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	106	125
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	106	125

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
अन्य भारतीय उत्पादक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	104	101
कुल मांग	मी.ट.	152,001	135,234	160,745	187,337
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	106	123

### बाजार का हिस्सा

घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	100	101
चीन जन. गण. का हिस्सा	%	15.96%	5.28%	4.08%	0.30%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	26	2
कोरिया गणराज्य का हिस्सा	%	1.17%	0.70%	1.15%	0.87%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	98	74
मलेशिया से आयात का हिस्सा	%	0.02%	0.02%	0.05%	0.10%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	342	658
संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा	%	17.15%	6.00%	5.28%	1.27%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	31	7
अन्य देशों से आयात का हिस्सा	%	12%	16%	24%	28%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	198	235
अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	98	82

57. यह नोट किया जाता है कि :

- चीन जन. गण. से आयातों में 2015-16 में 24,256 मी.ट. से जांच की अवधि के दौरान 564 मी.ट. तक कमी आई है।
- कोरिया गणराज्य से आयातों में 2015-16 में 1,782 मी.ट. से आंशिक रूप से जांच की अवधि के दौरान 1,633 मी.ट. तक कमी आई है।
- जांच की पूरी अवधि और क्षति की अवधि के दौरान मलेशिया से आयात अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अत्यंत कम रहा है।
- कुल मिलाकर संबद्ध देशों से आयातों में स्वतंत्र मात्रा में 2015-16 में 26,062 मी.ट. से जांच की अवधि के दौरान 2,387 मी.ट. तक कमी आई है।
- चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और मलेशिया से जांच की अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा क्रमशः 0.30 प्रतिशत, 0.87 प्रतिशत और 0.10 प्रतिशत है।
- अन्य देशों से आयातों का बाजार हिस्सा 2015-16 में 12 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 28 प्रतिशत हो गया है।
- पूर्व के वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।

### पाठित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

- संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि ये इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराये गये लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों और अन्य देशों से संबद्ध देशों और अन्य देशों देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयातों की मात्रा की जांच की है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
<u>आयात मात्रा</u>					
चीन जन. गण.	मी. ट.	24,256	7,152	6,558	564
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	29	27	2
कोरिया गणराज्य	मी. ट.	1,782	942	1,852	1,633
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	104	92
मलेशिया	मी. ट.	24	21	85	191
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	362	811
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. ट.	26,062	8,115	8,495	2,387
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	33	9
अन्य देश	मी. ट.	18,264	21,457	38,287	52,893
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	210	290
कुल आयात	मी. ट.	44,326	29,573	46,782	55,280
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	106	125
कुल आयातों की तुलना में चीन जन. गण. से आयात	%	54.72%	24.18%	14.02%	1.02%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	26	2
कुल आयातों की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयात	%	4.02%	3.19%	3.96%	2.95%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	98	73
कुल आयातों की तुलना में मलेशिया से आयात	%	0.05%	0.07%	0.18%	0.35%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	343	650
कुल आयातों की तुलना में संबद्ध देशों से आयात	%	58.80%	27.44%	18.16%	4.32%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	31	7

कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में चीन जन. गण. से आयात (एच आर 304)	%	16.73%	4.30%	3.79%	0.32%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	26	23	2
कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयात (एच आर 304)	%	1.23%	0.57%	1.07%	0.92%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	87	75
कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में मलेशिया से आयात (एच आर 304)	%	0.02%	0.01%	0.05%	0.11%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	303	660
कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयात (एच आर 304)	%	17.97%	4.88%	4.90%	1.34%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	27	27	7
मांग	मी. ट.	152,001	135,234	160,745	187,337
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	106	123
भारतीय खपत/ मांग की तुलना में चीन जन. गण. से आयातों का हिस्सा	%	15.96%	5.29%	4.08%	0.30%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	26	2
भारतीय खपत/ मांग की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयातों का हिस्सा	%	1.17%	0.70%	1.15%	0.87%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	98	74
भारतीय खपत/ मांग की तुलना में मलेशिया से आयातों का हिस्सा	%	0.02%	0.02%	0.05%	0.10%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	342	658
भारतीय खपत/ मांग की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा	%	17.15%	6.00%	5.28%	1.27%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	31	7

59. यह नोट किया जाता है कि :

क) चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में कमी आई है। जांच की अवधि के दौरान, कुल आयातों की तुलना में चीन जन. गण. से आयातों का हिस्सा 1.02 प्रतिशत है। कुल भारतीय उत्पादों और खपत की तुलना में चीन जन. गण. से आयातों में काफी हृद तक गिरावट आई है और यह 2015-16 में 100 सूचकांक से घटकर जांच की अवधि के दौरान 2 सूचकांक हो गया है।

ख. कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान, कुल आयातों की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयातों का हिस्सा 2.95 प्रतिशत है। कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयातों में 2015-16 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 75 सूचकांक तक कमी आई है। उसी प्रकार से, कुल खपत की तुलना में कोरिया गणराज्य से आयातों में 2015-16 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 74 सूचकांक तक कमी आई है।

ग. मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान, कुल आयातों की तुलना में मलेशिया से आयातों का हिस्सा 0.35 प्रतिशत है। कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में मलेशिया से आयातों में 2015-16 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 660 सूचकांक तक वृद्धि हुई है। हालांकि, मलेशिया से आयात हमेशा स्वतंत्र रूप में न्यूनतम रहा है।

### III. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

60. इस नियमावली के अनुबंध ॥ (ii) के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संबंध में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करें।

#### i. कीमत में कटौती

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पादन में कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से बहुत अधिक हृद तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी और अन्य प्रकार से काफी हृद तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से इस उत्पाद का पहुंच मूल्य और व्यापार के उसी स्तर पर सभी दूष्ट और करों के निवाल के रूप में घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था।

विवरण	यू.ओ.एम	चीन जन. गण.	कोरिया गणराज्य.	मलेशिया
आयात की मात्रा	मी. ट.	564	1,633	191
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	158,393	151,664	158,747
घरेलू बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	(***)	***	(***)
कीमत में कटौती	%	(***)	***	(***)
कीमत में कटौती	रेंज	(10)-0	0-10	(10)-0

62. यह नोट किया जाता है कि :

क) कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण भारत में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत में कटौती हो रही है।

ख) चीन जन. गण. और मलेशिया से आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू बिक्री कीमत में कटौती नहीं हो रही है।

ii. कम कीमत पर बिक्री

63. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री के कारण हो रहे नुकसान की भी जांच की है। इस उद्देश्य से, इस नियमावली के अनुबंध ॥। के संबंध में निर्धारित एन आई पी की तुलना डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी अंकड़ों से यथाप्राप्त आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। आयातों का भारित औसत पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की एन आई पी की तुलना नीचे दिये गये अनुसार दर्शाती है :

विवरण	यू.ओ.एम	चीन जन. गण.	कोरिया गणराज्य	मलेशिया
आयात की मात्रा	मी. ट.	564	1,633	191
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	158,393	151,664	158,747
एन आई पी	रु./ मी. ट.	***	***	***
क्षति मार्जिन	रु./ मी. ट.	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	0-10	10-20	0-10

64. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री के कारण हानि हुई है।

iii. कीमत में हास और न्यूनीकरण

65. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनकारी अथवा हासकारी प्रभाव पड़ रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव बनेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों तथा पहुंच मूल्य के परिवर्तन पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शायी जाती है :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
निर्माण करने और बिक्री करने की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	112	123
घरेलू बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	118
पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	1,41,610	1,27,131	1,41,033	153,820
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	100	109

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की लागत में 2015-16 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 123 सूचकांक तक वृद्धि हुई है जबकि घरेलू बिक्री कीमत में 2015-16 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 118 सूचकांक तक वृद्धि हुई है।

#### ज. 4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

67. इस नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटिट आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की चर्चा नीचे की गई है :

#### क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री

68. घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता, क्षमता के उपयोग के संबंध में कार्यनिष्पादन नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (कुल)	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	128	126
उत्पादन (पी.यू.सी)	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	124
उत्पादन (एन.पी.यू.सी)	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	129	127
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	128	126
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	106	125

69. उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित देखा जा सकता है :

- क्षति की जांच की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान क्षमता स्थिर रही है।
- उत्पादन, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री में मांग में वृद्धि को देखते हुए क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

### ख) लाभ, लगायी गयी पूँजी पर लाभ और नकद लाभ

70. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत, बिक्री कीमत, लाभ/ हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
लाभ/(हानि)	रु./ मी. ट.	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	308	-29	-206
लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	301	-30	-256
पी बी आई टी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	60	27
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	37	-53
ओर ओ आई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	88	36

71. यह देखा गया है कि लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ में सबसे पहले पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद 2016-17 के दौरान वृद्धि हुई और उसके बाद 2017-18 और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।

### ग) मांग में बाजार का हिस्सा

72. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर पाइट आयातों के प्रभावों की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	100	101
चीन जन. गण. का हिस्सा	%	15.96%	5.28%	4.08%	0.30%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	26	2
कोरिया गणराज्य का हिस्सा	%	1.17%	0.70%	1.15%	0.87%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	98	74
मलेशिया से आयात का हिस्सा	%	0.02%	0.02%	0.05%	0.10%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	342	658
संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा	%	17.15%	6.00%	5.28%	1.27%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	31	7
अन्य देशों से आयात	%	12%	16%	24%	28%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	198	235

73. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2016-17 के दौरान काफी हद तक वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद 2017-18 के दौरान इसमें गिरावट आई है और जांच की अवधि में इसमें आंशिक रूप से सुधार आया है। हालांकि, गैर संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में 2015-16 में 100 सूचकांक से बहुत अधिक बढ़कर वह जांच की अवधि के दौरान 235 सूचकांक हो गया है।

**घ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

74. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	97	98
मजदूरी	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	117	97
उत्पादकता/ कर्मचारी	मी. ट./ कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	124	127
उत्पादकता प्रतिदिन	मी. ट./ दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	128	126

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार और वेतन में जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2015-16 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 127 सूचकांक तक वृद्धि हुई है।

**ड) माल सूची**

76. संबद्ध वस्तुओं की माल सूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं :

विवरण	यू ओ एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
आरंभिक भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	155	57
अंतिम भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	41	76
औसत भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	89	68

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास माल सूची के स्तर में 2016-17 के दौरान वृद्धि हुई है और फिर 2017-18 और जांच की अवधि के दौरान उसमें कमी आई है।

**च) पाटन का परिमाण**

78. पाटन का परिमाण जिस सीमा तक भारत में आयातों का पाटन हो रहा है और घरेलू उद्योग को इसके परिणाम के तौर पर क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है का एक संकेतक है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध

देशों से आयात भारत में पाटित कीमतों पर हो रहे हैं और पाटन का मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम सीमाओं से ऊपर है।

### छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है जबकि अन्य देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने लगाई गई अपनी पूंजी पर कम लाभ अर्जित किया है।

### ज) वृद्धि

80. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं :

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
उत्पादन (एचआर 304)	%		15%	4%	3%
घरेलू बिक्री	%		-2%	8%	18%
घरेलू लाभ प्रति मी. ट.	%		208%	-109%	-617%
घरेलू लाभ प्रति लाख	%		201%	-110%	-742%
नकद लाभ	%		72%	-78%	-243%
पी बी आई टी	%		47%	-59%	-55%
आर ओ आई	%		7%	-9%	-5%

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन और घरेलू बिक्री जैसे घरेलू उद्योग की मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ है। हालांकि, लाभप्रदता, निवेश पर लाभ जैसे घरेलू उद्योग के कीमत संबंधी मानदंड जांच की अवधि के दौरान बदतर हुए हैं।

### झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं कि जांच यह दर्शाती है कि चीन जन. गण. और मलेशिया से आयात किये गये माल का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है और कोरिया गणराज्य से आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत से कम है। संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में कम कीमत पर बिक्री हो रही है।

### अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

83. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों को नोट किया है जो घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति में सहायक हो सकता था।

### क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
<u>आयात की मात्रा</u>					
चीन जन. गण.	मी. ट.	24,256	7,152	6,558	564
कोरिया गणराज्य	मी. ट.	1,782	942	1,852	1,633
मलेशिया	मी. ट.	24	21	85	191
संबद्ध देश	मी. ट.	26,062	8,115	8,495	2,387

अन्य देश	मी. ट.	18,264	21,457	38,287	52,893
कुल	मी. ट.	44,326	29,573	46,782	55,280
<u>आयात की मूल्य</u>					
चीन जन. गण.	रु./ मी. ट.	130,354	115,942	126,838	147,342
कोरिया गणराज्य	रु./ मी. ट.	157,940	144,171	153,817	151,057
मलेशिया	रु./ मी. ट.	128,748	122,889	150,337	158,747
संबद्ध देश	रु./ मी. ट.	132,238	119,238	132,955	150,795
अन्य देश	रु./ मी. ट.	124,980	115,729	135,673	147,965

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में क्षति की जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कमी आई है जो लागू पाटनरोधी शुल्कों के कारण हो सकता है। अन्य देशों (विशेष ताइवान और इण्डोनेशिया से) भारत में हो रहे आयातों की मात्रा में वृद्धि देखी गई है।

**ख) निर्यात कार्यनिष्पादन**

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, हालांकि यहां इसमें ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना का संबद्ध इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू बाजार के कार्यनिष्पादन से ही है। इस प्रकार से, घरेलू उद्योग के निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए हुई क्षति को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

**ग) प्रौद्योगिकी**

86. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पी यू सी का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी का संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए एक कारक नहीं है।

**घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकता थी।

**ङ) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

88. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभवना नहीं है।

**च) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन**

89. आवेदकों द्वारा उत्पादन की जा रही और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का संभावित कारण नहीं है क्योंकि आवेदकों द्वारा दी गई कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना/ आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति रहित कीमत पर विचार क्षति के मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल की सर्वोत्तम उपयोगिता पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ भी किया गया है। क्षति के अवधि के दौरान यूटिलिटी के सर्वोत्तम उपयोगिता पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन

**क्ष. क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण**

90. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति रहित कीमत पर विचार क्षति के मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल की सर्वोत्तम उपयोगिता पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ भी किया गया है। क्षति के अवधि के दौरान यूटिलिटी के सर्वोत्तम उपयोगिता पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन

की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया गया है और उसी उत्पादन पर प्रति इकाई निर्धारित लागत तय करने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित लाभ (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति अनुबंध III में यथानिर्धारित और अनुपालन की जा रही क्षति रहित कीमत को तय करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है जो नीचे दिया गया है:

### क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एन आई पी-यू एस डॉ/मी. ट.	पहुंच मूल्य यू एस डॉ/मी. ट.	क्षति मार्जिन यू एस डॉ/मी. ट.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज - %
1.	चीन जन. गण.	कोई भी	***	2237	***	***	0-10
2.	कोरिया गणराज्य	कोई भी	***	2142	***	***	10-20
3.	मलेशिया	कोई भी	***	2242	***	***	0-10

### क्ष. 1 क्षति संबंधी निष्कर्ष :

91. वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

- क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मात्रा में कमी रही है।
- अन्य देशों से आयातों में काफी हद तक वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देशों से पाठिन मार्जिन सकारात्मक है।
- शुल्कों के लागू रहने के बावजूद पाठित कीमतों पर आयात किया जाना जारी था।
- संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव पड़ रहा है।
- लाभ, निवेश पर लाभ, नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन और जांच की अवधि में गिरावट आई है।

अ. पाठन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

अ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

92. घरेलू उद्योग द्वारा पाठन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. चीन जन. गण. से निर्यातकों द्वारा लगातार पाटन के आगे और अधिक होने जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को मौजूदा शुल्क को वापस लिये जाने की स्थिति में आगे और अधिक क्षति की स्थिति उत्पन्न होगी, की स्पष्ट संभावना है।

ख. यद्यपि संबद्ध आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के बाद गिरावट आई है लेकिन वे कीमतें जिन पर आयात हो रहा है पाटित और क्षतिकारक कीमत हैं। इस प्रकार से शुल्कों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को और अधिक पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है। पाटन मार्जिन सकारात्मक है और घरेलू उद्योग को वर्तमान में क्षति हो रही है।

ग. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई, हालांकि जांच की अवधि के बाद आयातों में आयात कीमत में आगे गिरावट के साथ वृद्धि दर्शायी है।

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि से पूर्व (1 छमाही वार्षिकीकृत)
आयात की मात्रा	मी.ट.	26,062	8,115	8,495	2,387	10,384
आयात कीमत	रु./मी.ट.	132,235	119,236	132,961	150,817	139,503

यह देखा जा सकता है कि आयातों में जांच की अवधि की बाद की अवधि में 31 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और आयात कीमतों में उसी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत तक गिरावट आई है। आयातों में ऐसी बिक्री जब भी तथा आयात की कीमतों में गिरावट से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में, आयातों में आगे और अधिक वृद्धि होगी, जिससे घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

घ. विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक बाजार परिदृश्य में 2010 में बहुत अधिक परिवर्तन देखा जब अचानक विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति मांग से बहुत अधिक हो गई। तब से मांग गेप आपूर्ति का अंतर वैश्विक स्तर पर बढ़ गया है। यह परिवर्तन चीन के द्वारा किया गया है जो मांग से बहुत अधिक विशाल क्षमताओं को स्थापित कर एक निवल आयातक होने से निवल निर्यातक बन गया है। चीन संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक है तथा इसके अलावा चीन अपनी बेल्ड और रोड पहलों तथा अपनाई जा रही नीतियों के साथ अन्य देशों के माध्यम अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। चीन और कोरिया दोनों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। स्वतंत्र रूप से बिक्री क्षमताओं का निर्धारण सी आर यू इंटरनेशनल “स्टेनलैस स्टील फ्लेट प्रॉडक्ट्स मार्किट आउटलुक फरवरी, 2020 स्टेस्टिकल रिप्पू” में प्रकाशित सूचना के अनुसार इन देशों में स्लेब की मौजूदा क्षमताओं से स्पष्ट खपत की कटौती कर किया गया है।

ड. यह नोट करना संगत है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल मूलभूत उत्पादन प्रक्रिया में स्क्रेप/ओरो-एलांस जैसे इनपुट्स को ग्लाना शामिल है। स्टील बनाने वाली भट्टी का उत्पादन एक स्लेब है। स्लेब आयाताकार क्रॉस सेक्सन के साथ एक अर्द्ध तैयार स्टील उत्पाद है और उसका उपयोग स्टेनलैस स्टील हॉट रोल्ड फ्लेट प्रॉडक्ट्स अर्थात हॉट रोल्ड शीट्स और स्ट्रिप्स के उत्पादन की प्रक्रिया में आरंभिक सामग्री के रूप में किया जाता है। हॉट रोलिंग प्रॉसेस रि-हिट फर्निश में शुरू होता है जहां स्लेब्स को 1100-1300 डिग्री से, स्टेनलैस स्टील ग्रेड के आधार पर हिट किया जाता है। हॉट रोल्ड प्रॉडक्ट्स मूदू (अनइल) होता है और डी स्केल्ड (शीट के साथ पिकल्ड) होता है। हॉट रोल्ड स्टेनलैस स्टील की कोल्ड रोलिंग एच आर स्टील की रोलिंग के द्वारा होल्ड रोलिंग मिलों में होता है। कोल्ड रोल्ड प्रॉडक्ट्स सीधे स्क्रेप अथवा स्लेब से सीधे नहीं बनाया जा सकता है।

च. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं को देखते हुए, यह संभव है कि वर्तमान शुल्क को समाप्त किये जाने की स्थिति में आयातों में कई गुना वृद्धि होगी।

छ. संबद्ध देशों में उत्पादक व्यापक रूप से निर्यात उन्मुख इकाईयां हैं। संबद्ध देशों से एचआर क्वायल और एच आर प्लेट का निर्यात नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

अवधि	चीन जन. गण.	मलेशिया	कोरिया गणराज्य
2014	16,78,561	21,679	7,66,934
2015	15,11,377	20,611	7,63,471
2016	18,31,883	30,633	7,80,221
2017	18,64,440	35,212	7,61,271
2018	16,25,769	38,177	8,30,894
2019	12,38,362	48,885	8,33,309
2020	12,22,010	38,436	7,51,932

ज. यह भी देखा जा सकता है कि मलेशिया एच आर प्रॉडक्ट्स (क्वायल और प्लेट्स) का निर्यात करता रहा है। मलेशिया में प्रमुख उत्पादक, एसरिनोक्स और बहरु स्टेनलैस अन्य देशों में संबंधित पक्षकार हैं जो विभिन्न देशों को इन वस्तुओं का निर्यात करते हैं। संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है।

झ. स्टेनलैस स्टील में व्यापार परिवर्तन के स्तर को वैश्विक रूप में लगाये गये और चालू व्यापार उपचारात्मक उपायों की संख्या से मापा जा सकता है। अनेक देशों ने चीन, कोरिया और मलेशिया (संबद्ध देश) पर व्यापार सुरक्षा शुल्क लगाया है। संबद्ध देशों पर लगाया गया विभिन्न शुल्क उन्हें उपलब्ध बाजार को प्रतिबंधित करता है। चूंकि भारत एक अनुकूल बाजार है अतः उत्पादकों को पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटिट कीमतों पर और अधिक निर्यात होने की संभावना है। इस प्रकार से अत्यधिक क्षमता के साथ इन उत्पादकों के लिए प्रतिबंधित बाजार के तथ्य के साथ साथ अतिरिक्त क्षमताएं यह दर्शाती हैं कि भारत को निर्यात में वृद्धि होगी क्योंकि भारत अत्यधिक मांग के साथ एक आकर्षक बाजार है।

ज. इस उत्पाद की देश में सतत और नये पाटन का लंबा इतिहास है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने के फलस्वरूप संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट हुई, हालांकि अन्य देशों से बहुत कम कीमत पर काफी हद तक आयातों में वृद्धि हुई है। वैश्विक रूप से, उत्पादकों को बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ता है और इस उत्पाद के पाटन का सहारा लेना पड़ा है। उत्पादक कीमत आकर्षक स्थानों को निर्यात परिवर्तित करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया, स्टेनलैस स्टील फ्लेट उत्पादों पर आरंभ की गई जांच में वर्तमान संबद्ध वस्तुओं को बाहर रखा जाता है। इस प्रकार से, स्टेनलैस स्टील फ्लेट उत्पादों पर शुल्कों को लगाये जाने की स्थिति में और उसके साथ ही संबद्ध वस्तुओं से वर्तमान शुल्कों को वापस लिये जाने का आशय यह होगा कि बड़ा हुआ पाटन संबद्ध देशों को परिवर्तित हो रहा है।

ट. भारत स्टेनलैस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इसके अलावा, भारत एकमात्र बाजार भी था जहां स्टेनलैस स्टील की खपत प्रतिवर्ष 9-10 प्रतिशत की सी ए जी आर से बढ़ रहा था। अपनी शोर्ट रेंज आउटलुक (एस आर ओ) में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्ड स्टील) ने उल्लेख किया कि स्टेनलैस स्टील की मांग आने वाले समय में पूरे विश्व में कम होने की आशा है। स्टील की मांग के चीन और कोरिया में भी कम होने की आशा है। वर्तमान वैश्विक महामारी के साथ, स्टेनलैस स्टील और संबद्ध

वस्तुओं की खपत में न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। यह भारतीय बाजार को अत्यधिक क्षमताओं से जूझ रहे निर्यातकों के लिए आकर्षक बना रहा है।

ठ. शुल्कों को लगाये जाने के बाद आयातों में गिरावट और ऐसे आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन का आशय शुल्क को वापस लिये जाने की स्थिति में पाटन की संभावना से है और यह अपने आप में पाटनरोधी शुल्क के विस्तार को न्यायोचित ठहराता है। निर्णयक समीक्षा जांच करने संबंधी यू.एस की नीति का संदर्भ इस संबंध में लिया गया है। पूरे विश्व में जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अपनाया गया सतत दृष्टिकोण यह है कि आयातों में गिरावट अथवा कम आयातों की स्थिति में, इस तथ्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना है। भारत सहित अन्य अधिकार क्षेत्रों में विगत में जांच करने वाले प्राधिकारियों के जांच परिणामों और निर्णयों के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।

ड. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत से बहुत कम कीमत पर होता है। आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है और इसके फलस्वरूप आगे आयात के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना है। यह भी संभव है कि संबद्ध देशों में ये उत्पादक आक्रामक रूप से लगभग निकट भविष्य में समग्र भारतीय मांग का लक्ष्य बनायेंगे और उसे अपने कब्जे में लेंगे।

## अ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं की गणना के लिए ताइवान में इन क्षमताओं पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया उक्त दृष्टिकोण को कानून में अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह विगत में प्राधिकारी द्वारा की जा रही अन्य जांच तथा स्टेनलैस स्टील के फ्लेट उत्पादों के आयातों (फा. सं. 6/12/2019 – डी जी टी आर) के आयातों के विरुद्ध अपने आपको घरेलू उद्योग द्वारा दायर किये गये चल रहे पाटनरोधी जांच जिसमें चीन और ताइवान को अलग अलग संबद्ध देशों के रूप में लिया गया है के विपरीत है।

ख. अनुबंध II के पैरा vii(ब) में किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता का आगे विश्लेषण अपेक्षित है। हालांकि, घरेलू उद्योग के आवेदन में ऐसी कोई जांच नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने बार बार यह उल्लेख किया है कि संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप बिक्री योग्य क्षमताओं की उपस्थिति मात्र पर्याप्त नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग से इस तथ्य को सिद्ध करना अपेक्षित है कि उक्त स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता को शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में भारत में परिवर्तित किया जायेगा और ऐसा कोई अन्य निर्यात बाजार नहीं है जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपा सके। इस कारण से घरेलू उद्योग इस शर्त को पूरा करने में असफल है।

ग. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं को दर्शाने के लिए समग्र रूप से स्टील के आंकड़ों पर विश्वास किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि आमतौर पर स्टील के ऐसे व्यापक आंकड़े को विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

घ. हालांकि, संभावना के विश्लेषण संबंध में घरेलू उद्योग का पूर्ण विश्लेषण आमतौर पर स्टील के आंकड़ों और न कि विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों से संबंधित है। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि स्टील के उक्त आंकड़े को आमतौर पर वर्तमान मामले में विशिष्ट विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

ड. घरेलू उद्योग ने आमतौर पर कोरिया गणराज्य में स्टील की मालसूची उपलब्ध कराई है। जबकि अन्य दो संबद्ध देशों अर्थात् चीन जन. गण. और मलेशिया में मालसूची के संबंध में बिलकुल कोई विश्लेषण नहीं है, कोरिया गणराज्य से संबंधित सूचना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

च. प्राधिकारी को यह समझना होगा कि भारत के विपरीत यू एस ए में पाटनरोधी शुल्क बाद की तिथि से लगाया जाता है, इसका आशय यह होता है कि किसी निर्यातक जिसका पाटन मार्जिन सकारात्मक है और जिसकी वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, अभी भी इस मामले की अगली वार्षिक समीक्षा में शुल्कों को वापस करने का दावा उस स्थिति में कर सकते हैं जब इस प्रकार की समीक्षा की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन उक्त निर्यातक के लिए मूल रूप से निर्धारित पाटन मार्जिन से कम था। इसके विपरीत, भारत में पाटनरोधी शुल्क जांच को बाद की तिथि से लागू होने की प्रकृति की है। इस कारण से, यू एस ए में प्रथा पर विचार पाटन अथवा क्षति की संभावना के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत पाटनरोधी शुल्कों के निर्धारण और संकलन के लिए स्पष्ट रूप से अलग प्रक्रिया का पालन करता है।

छ. मलेशिया में क्षमताओं में हाल के वर्षों में काफी हद तक गिरावट आई है और वह विशेष रूप से अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। प्राधिकारी को मलेशिया में क्षमताओं की गिरावट की प्रवृत्ति, भारत को इसके द्वारा सतत रूप से कम निर्यात और इसकी बहुत अधिक कीमतों को नोट करना चाहिए तथा इन कारकों का सुन्यवस्थित पठन यह सिद्ध करता है कि मलेशिया के पास “अत्यधिक क्षमता” नहीं है।

ज. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करने के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन शोर्ट रेंज आउटलुक (पृष्ठ सं. 138 पर याचिका का अनुबंध 4.3) का संदर्भ लिया है कि पूरे विश्व में स्टेनलैस स्टील के लिए मांग में कमी आने की आशा है। हालांकि, यह अनुरोध किया गया है कि जिस रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया है उसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि “स्टील की मांग में वृद्धि में व्यापार तनावों में कमी आने पर निर्भर करते हुए 2020 में सुधार होने की आशा है”। अतः याचिकाकर्ताओं के अपने आंकड़ों से भी यह प्रतीत होता है कि इस दावे का कोई आधार नहीं है और इसमें कोई दम नहीं है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह रिपोर्ट मलेशिया में मांग के बारे में मौन है। अतः यह प्रतीत होता है कि मलेशिया का उत्पादन और क्षमता वैश्विक आउटलुक में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस कारण से याचिकाकर्ताओं पर कोई सार्थक प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

झ. याचिकाकर्ताओं ने स्टेनलैस स्टील फ्लेट उत्पादों के विरुद्ध वर्तमान शुल्कों की एक सूची उपलब्ध कराई है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि समग्र सूची लागू शुल्कों से संबंधित हैं जो प्रायः हरेक देश के विरुद्ध हैं और यह किसी संबद्ध देश से संबंधित नहीं है। किसी भी स्थिति में समग्र सूची में मलेशिया के विरुद्ध केवल एक जांच अर्थात् वियतनाम द्वारा की गई जांच का उल्लेख है। यह शुल्क 6 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होने वाला था।

ज. पाटन के स्रोतों के कथित “परिवर्तन” के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा भारत में प्राधिकारी द्वारा लगाये गये शुल्कों पर पूर्ण रूप से आधारित है। इस संबंध में हम अनुरोध करते हैं कि शुल्कों को लगाना “एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक पाटन के किसी परिवर्तन” को नहीं दर्शाता है। बल्कि, इतने अधिक पिछले शुल्कों का होना यह दर्शाता है कि यह उत्पाद संवेदनशील उत्पाद है और यह उन घटनाओं के लिए विशिष्ट जांच और शुल्कों के अध्यधीन रहा है।

ट. मलेशिया के संबंध में, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं करते हैं कि या तो आयातों की बहुत अधिक मात्रा रही है अथवा की आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मलेशिया के आयात ऐतिहासिक रूप से कम रहे हैं और उसे वैसा ही माना जाना चाहिए।

ठ. भारत की कीमत आकर्षकता के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा गोपनीय के रूप में माने गये आंकड़ों पर पूर्ण रूप से निर्भर है। हम अनुरोध करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमत और बिक्री की लागत की जांच आवश्यक है।

ड. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारत – आशियान एफ टी ए के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थितियों के कारण मलेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार के दावे को भारत – आशियान एफ टी ए पर हस्ताक्षर करने के बाद भी मलेशिया से आयातों की ऐतिहासिक रूप से कम मात्रा को देखते हुए नहीं किया जा सकता है।

ढ. इस पर विचार करना उपयुक्त नहीं है कि मलेशिया जिसका मूल जांच की अवधि में भी कुल आयात का 3.59 प्रतिशत हिस्सा था और वर्तमान में उसका कुल आयातों का 0.35 प्रतिशत हिस्सा है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

### **अ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

94. प्राधिकारी के ध्यान में लाये गये सभी कारकों की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए किया गया है कि क्या शुल्कों को समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यथाउपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है।

95. वर्तमान जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखना आवश्यक है। इसमें इस तथ्य पर भी विचार करना अपेक्षित है कि क्या लगाये गये शुल्क से प्रतिकारक पाटन को समाप्त करने का अभीष्ट उद्देश्य पूरा हो रहा है। ऐसी संभवना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इस नियमावली के अनुबंध ॥ के उपनियम (vii) में अन्य बातों के साथ साथ उन कारकों का प्रावधान है, जिन पर विचार किया जा सकता है अर्थात् :

- क. पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि का अत्यधिक दर;
- ख. पर्याप्त स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य, अथवा आसन्न, अत्यधिक वृद्धि, निर्यातक की क्षमता जो भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए दर्शाता हो;
- ग. क्या ये आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक हासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और आगे आयातों के लिए संभावित रूप से मांग में वृद्धि होगी; तथा
- घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।

96. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों जिनका घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना पर प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है। संभावना के मानदंडों की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

#### **(i) पी यू सी का जांच की अवधि के बाद की अवधि का आयात**

97. भारत में जांच की अवधि के बाद के दौरान हुए आयातों की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त किये हैं और उससे यह देखा जाता है कि जांच की अवधि से तुलना करने पर जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि के आयात संबंधी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

विवरण	यू.ओ.एम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद की अवधि (अप्रैल-सितंबर 2019)
चीन जन. गण.	मी. ट.	24,256	7,152	6,558	564	1,326
कोरिया गणराज्य	मी. ट.	1,782	942	1,852	1,633	3,803
मलेशिया	मी. ट.	24	21	85	191	63
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. ट.	26,062	8,115	8,495	2,387	5,192

98. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बावजूद, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयात बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं।

**(ii) निर्यातकों के पास अतिरिक्त क्षमता**

99. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं की स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं उपलब्ध कराई हैं, जिसका निर्धारण सी आर यू इंटरनेशनल “स्टेनलैस स्टील फ्लेट प्रॉडक्ट्स मार्किट आउटलुक फरवरी 2020 स्टेटिकल रिव्यू” में दी गई मौजूदा क्षमताओं से संबंधित सूचना से खपत को घटाने के बाद किया गया है। रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य में उपलब्ध संबद्ध वस्तुओं की स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात के लिए किया जा सकता है।

**(iii) क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक हासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इसके फलस्वरूप आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना बनेगी**

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति की जांच की अवधि और पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में कमी आई है। हालांकि, आयात मात्रा में जांच की अवधि के बाद की अवधि में अत्यधिक उद्धाल देखा गया है। ऐसे आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है।

**(iv) माल सूची**

101. माल सूची के संबंध में, घरेलू उद्योग ने कोरिया गणराज्य में माल सूची के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य में उपलब्ध माल सूची का उपयोग भारत को उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है।

102. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं :

- I. चीन जन. गण. से आयातों में 2015-16 में 24,256 मी. ट. से जांच की अवधि के दौरान 564 मी. ट. तक कमी आई है। कोरिया गणराज्य से आयातों में 2015-16 में 1,782 मी. ट. से आंशिक रूप से जांच की अवधि के दौरान 1,633 मी. ट. तक गिरावट आई है। जांच की पूरी अवधि और क्षति की अवधि के दौरान मलेशिया से आयात जांच की बाद की अवधि सहित कम रही है।
- II. संबद्ध देशों से आयातों में स्वतंत्र मात्रा में और भारत में कुल उत्पादन और मांग की तुलना में क्षति की जांच की अवधि और पी ओ आई के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों में जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- III. संबद्ध देशों से आयात अभी भी पाटित कीमतों पर हो रहा है।
- IV. कोरिया गणराज्य संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण भारत में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत में कटौती हो रही है।
- V. चीन जन. गण. और मलेशिया से आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हो रही है।
- VI. उत्पादन और घरेलू बिक्री जैसे घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ है। हालांकि, लाभप्रदत्ता, निवेश पर लाभ जैसे घरेलू उद्योग के कीमत संबंधी मानदंडों जांच की अवधि के दौरान खराब हुए हैं।

**प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ**

**ट.1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

103. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

क) मै. बाहरू स्टेनलैस एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अंतर्गत वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार नहीं है क्योंकि यह संबद्ध वस्तुओं का निर्यातक, उत्पादक अथवा व्यापारी नहीं है।

मैं, मेरिनो पेनल प्रोडक्ट्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के सेस्टेट ने यह माना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कोई भी पक्षकार किसी जांच में अपने दर्जे को स्थापित किए बिना केवल प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

ख) यदि कंपनी यह दावा करती है कि इसने भारत को इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है तब कंपनी एक हितबद्ध पक्षकार नहीं रह जाती है। यदि कंपनी विदेशी उत्पादक के रूप में एक हितबद्ध पक्षकार होने का दावा करती है तब कंपनी इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या कंपनी ने भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया है, प्रश्नावर्ती का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था। कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह अपने तीसरे देशों के निर्यातों को दर्शाए।

ग) मलेशिया से कीमतों में जांच की अवधि की बाद की अवधि में गिरावट आई है। आयात यद्यपि कम मात्रा में पाटित और क्षतिकारक कीमत पर किया जाना जारी है। इस प्रकार, शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात पाटित और क्षतिकारक कीमत पर और अधिक होने की संभावना है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

घ) स्लैब की क्षमता पर विचार करते हुए, चीन जन.गण और कोरिया गणराज्य के उत्पादकों के पास अत्यधिक अतिरिक्त क्षमता है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल मौलिक उत्पादन प्रक्रिया में स्कैप/अयस्क फेरो-अलायस जैसे इनपुट्स को गलाना शामिल है। इस्पात का निर्माण करने वाली भट्टी का उत्पादन एक स्लैब है जो अत्यधिक क्षमता की जांच करने के लिए एक उपयुक्त न्यूनतम मानदंड है।

ङ.) विश्व में अनेक देशों के पास स्टेनलेस स्टील उत्पाद के लिए अतिरिक्त क्षमता है और वही कारण है कि अनेक व्यापार उपचारात्मक उपाय अनेक देशों के विरुद्ध लागू हैं अथवा चल रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न देशों में पाटित आयातों के लिए अपने बाजार को अवरुद्ध कर दिया है।

च) चीन जन.गण और कोरिया गणराज्य द्वारा भारत में प्रचलित कीमत से बहुत कम कीमत पर बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किए जा रहे हैं और इस प्रकार से भारत निर्यात के लिए एक अधिक कीमत आकर्षक देश बन रहा है। उत्पादक बाजार की तलाश करेंगे जहां उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कीमत मिल सकें। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप इन देशों से पाटित आयातों के अंतर-प्रवाह की संभावना है।

घ) आयात की मामूली मात्रा निर्णयक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं करने का कारण नहीं हो सकता है और उसकी पुष्टि सेस्टेट द्वारा एआईए इंजीनियरिंग बनाम संघ सरकार के मामले में की गई थी।

ज) वर्तमान शुल्क का विस्तार न करने के कारण समानांतर जांच का प्रभाव भी कम होगा जो वर्तमान संबद्ध देशों से भी स्टेनलेस स्टील फैलैट उत्पादों के आयातों पर विचार करता है और इस प्रकार की जांच विशिष्ट रूप से उत्पाद क्षेत्र से एचआर 304 को शामिल नहीं करता है।

झ) वर्तमान शुल्कों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है और मात्रा में संशोधन वर्तमान परिस्थितियों में अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए आवश्यक नहीं है।

ञ) आवेदक अन्य पक्षकारों को भेजे गए पत्रों, अन्य पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों, घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत का प्रकटन एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से करते हैं।

ट) वैश्विक महामारी की जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में मांग में गिरावट आ रही है, की वर्तमान स्थिति में, विभिन्न देश जिस किसी रूप में संभव होगा, निर्यात करने के लिए बेकरार होंगे। इसके अलावा, बाहर के संबंध में डीआर आई के अनेक मामले हुए हैं जो यह दर्शाता है कि निर्यातक का गलत कार्य-पद्धतियों में लगे रहने और शुल्कों से बचने का भी एक इतिहास है।

ठ) भारत स्टेनलेस स्टील फैलैट उत्पाद जिसमें 304 सीरीज का हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील फैलैट उत्पादों का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। संबद्ध वस्तुओं की मांग में भी चल रही महामारी के कारण गिरावट आई है। अगर यह भी मान लिया जाता है कि भारत में मांग में बढ़ोतरी में भी कमी आई है, भारत में मांग के महत्वपूर्ण स्तर पर विचार करते हुए, यह संभव है कि भारतीय बाजार इन संबद्ध देशों

जिनके पास भारी मात्रा में अतिरिक्त क्षमताएं हैं और जो अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं, से आयातों को आकर्षित करेगा।

## ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध

104. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोधों पर विचार नहीं किया है:

- घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए आंकड़ों से संबंधित अनुरोध विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नहीं हैं।
- घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं का गलत आकलन किया गया है क्योंकि ऐसे कारक से संबंधित आंकड़े संबद्ध देश के रूप में ताइवान को शामिल किया।
- अनुबंध II के पैरा vii(घ) के संबंध में किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता से संबंधित किसी विश्लेषण का न होना।
- कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के न होने के संबंध में अनुरोध।
- अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के संबंध में अनुरोध।

ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात का मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं कि आवेदकों ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा जारी की गई गोपनीयता के संबंध में निर्देश का पालन नहीं किया।

ग) प्रकटन विवरण में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी ने संभावना का विश्लेषण करने के लिए जांच की बाद की अवधि (अप्रैल-सितंबर, 2019) के आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि संबंधी आंकड़ों को अपने आप पूर्व निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने के लिए एकपक्षीय रूप से चुनी गई अवधि के लिए लिया गया है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार का कोई आंकड़ा हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। नियम 7 के संदर्भ में, ऐसा कोई दस्तावेज जिस पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है, अगोपनीय पाठ में इन हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह अनुरोध किया जाता है कि नियम 7 के अनुसार, यदि इस प्रकार के दस्तावेज का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब प्राधिकारी अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस प्रकार के दस्तावेजों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

घ) जबकि प्राधिकारी ने जांच की अवधि की बाद की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों का मात्रा संबंधी विश्लेषण किया है, उसके लिए कीमत का कोई विश्लेषण नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि की बाद की अवधि के आंकड़ों के आधार पर निकाला गया कोई निष्कर्ष मात्रा और कीमत विश्लेषण दोनों के आधार पर होना है। इसके अलावा, जांच की अवधि के बाद की अवधि में बढ़ी हुई मात्रा सदृश्य कीमत विश्लेषण के अभाव में कोई महत्व नहीं रखती है।

ङ.) प्राधिकारी द्वारा संभावना के विश्लेषण के संबंध में जांच निम्नलिखित कारणों से कानूनी अपेक्षाओं तथा इस मामले के तथ्यों के विपरीत है।

- यह अनुरोध किया जाता है कि अनुबंध-II के पैरा (vii) में भारत में पाठित आयातों की वृद्धि की दर से संबंधित जांच अपेक्षित है जो वास्तविक रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाता है। हालांकि ऐसी कोई जांच प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में नहीं की गई है।
- प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों और मालसूचियों के साथ अतिरिक्त क्षमताओं को दर्शाने के लिए समग्र रूप में स्टील के आंकड़ों पर विचार किया है।

यह अनुरोध किया जाता है कि आमतौर पर स्टील के ऐसे व्यापक आंकड़ों को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह रिकॉर्ड का मामला है कि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद समग्र स्टील उत्पादन का एक उप समुचित्य है। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के संबंध में तर्क देने के लिए आमतौर पर स्टील के आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। इस संबंध में, प्रतिवादी भारत-लौह और इस्पात के आयातों के संबंध में कुछ उपाय (डीएस 518) पर डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट के पैरा 7.111 और 7.112 पर विश्वास करते हैं।

च) प्राधिकारी ने खंड-IV में क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए पद्धति उपलब्ध कराई है जिसका उपयोग क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा। इस संदर्भ में यह अनुरोध किया जाता है कि खंड-IV के केवल पहले मात्रा से यह देखा जाता है कि प्राधिकारी ने इस नियमाकारी के अनुरोध -III में दिए गए सिद्धातों का भी उल्लेख किया है। हालांकि प्रकटन विवरण के खंड-IV में इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है कि वास्तव में किस प्रकार से प्राधिकारी ने कच्चे माल की लागत, क्षमता के उपयोग की गणना लागत को मानक के रूप में बनाने के लिए किया है।

छ) यह अनुरोध किया जाता है कि मलेशिया का आयात क्षति की जांच की अवधि और जांच की अवधि के दौरान मामूली है। वास्तव में, मलेशिया से आयातों में जांच की अवधि की बाद की अवधि में और अधिक कमी आई है। यदि मलेशिया से आयात की प्रवृत्तियों का भी आंकलन 2009-10 की अवधि से की जाती है तब यह स्पष्ट है कि मलेशिया से आयात हमेशा भारत में मामूली मात्रा में हुआ है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि काई हो का कारण मलेशिया से आयात बिल्कुल नहीं है।

ज) प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संबंध में अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया है, प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या स्टाक यार्ड खर्च, विज्ञापन और प्रचार, बिक्री खर्च, भाड़ा एवं आगे प्रेषित करने के लिए खर्च, संदिग्ध ऋण/अग्रिम राशि, न वसूले जाने वाले ऋण आदि के लिए प्रावधान जैसे निर्माण पश्चात खर्च पर क्षतिरहित कीमत का आंकलन करते समय विचार किया गया है अथवा नहीं।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त किए गए हैं। प्राधिकारी ने पुनरावृत्तियों जिसकी पहले ही उपर्युक्त रूप से समाधान और समुचित रूप से इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में जांच की गई है, सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

106. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों और अनुरोधों का संज्ञान नहीं लेने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सतत कार्य-पद्धति के मामले के रूप में तथा कानूनी आवश्यकता के संदर्भ में इन सभी अनुरोधों का विधिवत् संज्ञान लिया है जिसे इन्होंने अपने विश्लेषण और जांच में निर्णय लेने के लिए संगत माना।

107. प्राधिकारी ने निर्यातक देशों के संभावित व्यवहार जहां तक भारत को उनके निर्यात का प्रश्न है, का आंकलन करने के लिए जांच की अवधि की बाद की अवधि के आयात आंकड़ों की जांच की है।

108. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों का अगोपनीय पाठ तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के अगोपनीय पाठ की प्रति उपलब्ध कराई जाए, यह नोट किया जाता है कि इन अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लोकडाउन के पूर्व सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद पत्र के सभी अगोपनीय पाठ जो डीजीटीआर की कार्य-पद्धति के अनुसार सार्वजनिक फाइल में रखे गए होते हैं, को हितबद्ध पक्षकारों के साथ ई-मेल के माध्यम से साझा किया गया है।

109. संबद्ध देशों से आयातों की कम मात्रा के संबंध में अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कभी आई है। हालांकि भारत में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर आयात का अभी भी होना जारी है। यह भी नोट किया जाता है कि गैर-संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की जांच की अवधि के दौरान काफी हृद तक वृद्धि हुई और स्टेनलेस स्टील फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर एक समानांतर पाटनरोधी जांच गैर-संबद्ध देशों के विरुद्ध किया जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में इस बात की संभावना है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तब संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि होगी।

110. इस अनुरोध के संबंध में कि बाहरु को इस नियमावली के नियम 2(ग) के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यह नोट किया कि बाहरु ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया है। हालांकि, बाहरु ने विगत में भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना इस नियमावली के नियम 2(ग) के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार बनने के लिए मानदंड नहीं है। इस प्रकार, वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने बाहरु को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना है और बाहरु द्वारा किए गए अनुरोधों का संज्ञान लिया है।

111. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में, यह नोट किया जा सकता है कि एनआईपी की गणना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इस नियमावली के अनुबंध-III में किया गया है और उसे वर्तमान समीक्षा जांच में एनआईपी का निर्धारण करते समय अपनाया गया है।

#### **ठ. भारतीय उद्योग के हित**

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आमतौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके। पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

113. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो तब भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

#### **ड. निष्कर्ष**

114. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा ऊपर में रिकॉर्ड किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन हुआ है और ये आयात शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में संभवतः होंगे।

ख. मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है लेकिन घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय जैसे कीमत संबंधी मानदंडों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ग. रिकॉर्ड पर दी गई सूचना घरेलू उद्योग को उस स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना दर्शाती है जब लागू पाटनरोधी शुल्क को इस चरण में समाप्त होने दिया जाता है।

घ. यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि इस चरण में पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहेगी।

### ३. सिफारिशें

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था।

116. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन और क्षति के जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को शुल्कों को जारी रखना अपेक्षित है।

117. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(i)(घ) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के उद्देश्य से पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई वस्तुओं पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि पांच (5) वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

### शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्धम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7219, 7220	स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद ***	चीन जन.गण	चीन जन.गण सहित कोई अन्य देश	कोई भी	160	अम. डॉ.	मी.टन
2	-वही-	स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद***	चीन जन.गण, कोरिया गणराज्य और मलेशिया के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण	कोई भी	160	अम. डॉ.	मी.टन
3	-वही-	स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद***	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई अन्य देश	कोई भी	255	अम. डॉ.	मी.टन

4	-वही-	स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद***	चीन जन.गण, कोरिया गणराज्य और मलेशिया के अलावा कोई अन्य देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	255	अम. डॉ.	मी.टन
5	-वही-	स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद***	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई अन्य देश	कोई भी	155	अम. डॉ.	मी.टन
6	-वही-	स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद***	चीन जन.गण, कोरिया गणराज्य और मलेशिया के अलावा कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	155	अम. डॉ.	मी.टन

**टिप्पणी** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऊपर में उल्लेख किया गया विचाराधीन उत्पाद तब भी पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन होगा जब इसका आयात किसी अन्य एचएस कोड के अंतर्गत किया जाता हो।

**\*\*\* टिप्पणी** स्टेनलेस स्टील 304 सीरीज के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद का आशय “हॉट रोल्ड आस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद ; चाहे आयाताकार रूप में प्लेट, शीट अथवा कॉयल (हॉट रोल्ड अनील्ड और पीकल्ड अथवा ब्लैक); या तो 304 अथवा 304 एच अथवा 304 एल अथवा 304एन अथवा 304एलएन अथवा ईएन 1.4311, ईएन 1.4301, ईएन 1.4307 अथवा एक्स5सीआरएनआई 1810 अथवा एक्स 04सीआर19एनआई9 ग्रेड का, अथवा यूएनएस, डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि जैसे किसी अन्य मानदंडों में उसका समतुल्य; चाहे नंबर वन अथवा ब्लैक फिनिश का हो अथवा नहीं: चाहे वह उत्कृष्ट अथवा गौण गुणवत्ता का हो अथवा नहीं; चाहे मिल एड अथवा ट्रिम एज के साथ एज की स्थिति वाला हो या नहीं; 1.2 एमएम से 10.5 एमएम की रेंज में कॉयल में और 3 एमएम से 105 एमएम प्लेट और शीट में मोटाई का; 1650 एमएम तक सभी चौड़ाई का(मिल एज के लिए 20 एमएम से अधिक तथा ट्रिम एज के लिए 5 एमएम से अधिक की चौड़ाई सहनशीलता) का हो अथवा नहीं” से है।

#### ण. आगे की प्रक्रिया

118. केन्द्र सरकार के आदेश जो इस सिफारिश के कारण हो सकते हैं, के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

बी.बी.स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**NOTIFICATION**

**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 29th September, 2020

**Case No.- (SSR) 07/2019**

**Subject: Final Findings in Sunset Review investigation concerning anti-dumping duty on imports of 'Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel – 304 grade' originating in or exported from China PR, Malaysia and Korea RP.**

**F. No. 7/16/2019-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof;

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

2. The Designated Authority (hereinafter also referred as the 'Authority') initiated an anti-dumping investigation on imports of "Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel – 304 grade" (hereinafter also referred as the 'subject goods' or 'product under consideration' or 'PUC'), originating in or exported from China PR, Malaysia and Korea RP (hereinafter also referred as the 'subject countries') *vide* notification No. 14/30/2013- DGAD dated 11th March 2014. The Authority thereafter notified the Final Findings No. 14/30/2013-DGAD dated 9th March 2015, recommending for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from China PR, Malaysia and Korea RP. Definitive anti-dumping duty was imposed by Ministry of Finance *vide* Customs Notification No. 28/2015- Customs (ADD) dated 5<sup>th</sup> June 2015 for five years.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

*"... any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."*
5. M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited and M/s. Jindal Stainless Limited (hereinafter referred to as 'Applicants' or 'Domestic Industry' or 'DI') filed a duly substantiated application on behalf of the domestic industry before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the present anti-dumping duties, applicable on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, Malaysia and Korea RP, for another five years.
6. In view of the duly substantiated application with *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the DI and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the Sunset Review Investigation *vide* Notification No.7/16/2019-DGTR dated 3rd October 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, to review the need for continued imposition of anti-dumping duty in respect of the subject goods,

originating in or exported from subject countries and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

#### **B. PROCEDURE**

8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Finding Notification No. 14/30/2013-DGAD dated 9th March 2015 which had recommended imposition of ADD on imports of subject goods originating in or exported from China PR, Malaysia and Korea RP.
9. The procedure, as described herein below, has been followed:
  - a. The Authority *vide* Notification No. 7/16/2019-DGTR dated 3rd October 2019 published a notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
  - b. The Embassy of the Subject Countries in New Delhi were informed about the initiation of the Sunset Review investigation in accordance with Rule 6(2) along with the copy of the initiation notification and non-confidential version of the application.
  - c. The Authority forwarded copies of the notification to the known producers / exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority by the Applicants) and provided an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with Rule 6(2) and Rule 6(4) of the Rules.
  - d. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and users association of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of issue of the letter.
  - e. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters of subject goods in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - (i) Taiyuan Iron and Steel (Group) Co. Ltd., China PR
    - (ii) Jiuquan Iron and Steel (Group) Co. Ltd., China PR
    - (iii) Lianzhong Stainless Steel Corporation, China PR
    - (iv) Baosteel Tower, China PR
    - (v) POSCO, Korea RP
    - (vi) Bahru Stainless Sdn. Bhd., Malaysia
  - f. No producer/exporter from subject countries has participated and filed the questionnaire response before the Authority in the present sunset review investigation except M/s. Bahru Stainless Sdn. Bhd., Malaysia who has filed injury submissions only.
  - g. Questionnaires were sent to the following known importers/users/Associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - (i) Ratnamani Metals and Tubes Ltd.
    - (ii) Sangeeta Metal (INDIA), Mumbai
    - (iii) Bhandari Foils & Tubes Ltd.
    - (iv) Ramani Steel House
    - (v) Prakash Steelage Ltd.
    - (vi) Nishant Infinn Pvt. Ltd.
    - (vii) Rajendra Mechanical Industries Ltd.
    - (viii) A.C Steel Sgop, Mumbai

(ix) Phoenix Foils Pvt. Ltd.  
(x) Quality Foils (India) Pvt. Ltd.  
(xi) Domet Trading Pvt. Ltd.  
(xii) Remi Edelstahl Tubulars Ltd.  
(xiii) Bharat Heavy Electricals Ltd.  
(xiv) VRV Asia Pacific Pvt. Ltd.  
(xv) Hisar Metal Industries Ltd.  
(xvi) JNB Steel Industries Pvt. Ltd.  
(xvii) Real Strips Ltd.  
(xviii) Unisteel Corporation  
(xix) Shree Venktesh Wires & Steels Pvt. Ltd.  
(xx) Inox India Ltd.  
(xxi) Apex Tubes Pvt. Ltd.  
(xxii) Steel Space Pvt. Ltd.  
(xxiii) Process Plant and Machinery Association of India  
(xxiv) Stainless Steel Exporters Welfare Association  
(xxv) All India Stainless Steel Industries Association of India  
(xxvi) The Tamil Nadu Stainless Steel Merchants and Manufacturers Association

h. M/s. Suncity Sheets Pvt. Ltd., M/s. Suncity Strips & Tubes Pvt. Ltd., M/s. Ratnamani Metals and Tubes Ltd., M/s. Quality Foils (India) Pvt. Ltd. have filed Importer/User Questionnaire response in the present investigation.

i. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. Interested parties, who requested inspection and copies of the documents from the public file, were provided with the same. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their written submissions to all other interested parties since the public file was not accessible due to ongoing global pandemic.

j. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted after due examination and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the confidential information, which was made available through public file.

k. Further information was sought from the Applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

l. Investigation was carried on for the period April 2018 – March 2019 (12 months) (hereinafter referred to as the ‘period of investigation’ or ‘POI’) with injury analysis covering the period 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 and the POI.

m. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide details of imports of subject goods for the past three years, the period of investigation, and the post POI period (April 2019 – September 2019), and the said information obtained from DGCI&S has been adopted for the purpose of the present investigation.

- n. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods.
- o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 11<sup>th</sup> September, 2020 which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- p. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- q. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such interested parties as non-cooperative and recorded in these final findings on the basis of the facts available.
- r. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 22<sup>nd</sup> September, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- s. ‘\*\*\*’ in these final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- t. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority for the subject investigation as 1 US\$ = Rs.70.82.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 10. The product under consideration in the present investigation is “Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled annealed and pickled or black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN 1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or black finish; whether or not of quality prime or non-prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650mm (width tolerance of + 20mm for mill edge and + 5mm for trim edge)”.
- 11. The subject goods are classifiable under Chapter 72 of the Custom Tariff Act, 1975 under tariff headings 7219 and 7220 of the Customs Tariff Act, 1975.

#### C.1 Submissions made by the Domestic Industry

- 12. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
  - a. The product description is the same as was decided by the Authority in the original investigation. Further, no significant developments has taken place over the period. Therefore, Petitioners refer to and rely upon the previous investigation with regard to the scope of product under consideration and like article.
  - b. The Authority has determined in the original investigation that the imported material and the goods produced by the domestic industry are like article. The applicants submit that the subject goods produced by the domestic industry should be treated as like article to subject goods imported from subject countries within the meaning of the AD Rules.

**C.2. Submissions made by other interested parties**

13. No submission has been made by other interested parties with regard to product under consideration and like article.

**C.3. Examination by the Authority**

14. This being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration (PUC) remains the same as that in the original investigation. The PUC in the original investigation was defined as under:

*"Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled annealed and pickled or black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN 1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or black finish; whether or not of quality prime or non-prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650mm (width tolerance of + 20mm for mill edge and + 5mm for trim edge)"*

*The subject goods are classifiable under Chapter sub-heading 7219 and 7220 of the Customs Tariff Act, 1975.*

15. Rule 2 (d) of the Rules relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

16. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the product produced by the Indian domestic industry. Product under consideration produced by the Indian domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

17. Thus, the Authority holds that product produced by the domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from the subject countries in accordance with the Rules.

**D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

**D.1. Submissions made by the Domestic industry**

18. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

a. The application has been filed by Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited. The production by the applicants constitutes a major proportion of total Indian production. Further, the applicants have not imported the subject goods nor are they related to any producer in the subject countries or to any importer. Thus, notwithstanding the fact that standing of the applicant is not necessary in sunset review, the Applicants submit that they constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**D.2. Submissions made by other interested parties**

19. No submission has been made by other interested parties with regard to scope of domestic industry & standing.

**D.3. Examination by the Authority**

20. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the*

*said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*

21. The present sunset review application has been filed by M/s. Jindal Stainless Limited and M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited. There are two more producers of the product under consideration in the country, namely, Shah Alloys and Steel Authority of India Ltd.
22. As per evidence available on record, Authority notes that Applicants command a major proportion in the total production of the subject goods in India. Applicants are neither related to an importer in India nor any exporter from the subject countries. Authority further notes that Applicants have not imported the subject goods during the period of investigation.
23. In view of the above, the Authority considers the Applicants as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Submissions made by the Domestic Industry**

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
  - a. The responses filed by the interested parties are grossly deficient. None of the users have filed the non-confidential version of the response in the prescribed manner and all the responses filed are in complete disregard to the trade notice 10/2018 dated 7th September, 2020. As per the trade notice the users are required to disclose information in certain manner.
  - b. Information provided by the users in their non-confidential version of the response is of no use to the domestic industry. Parties have not even provided adequate reasons for not disclosing such information in the response. Not only the information required to be disclosed as per the trade notice, but information available in public domain also have been claimed as confidential by the parties.
  - c. The Authority in the past in antidumping investigation concerning imports of Nitrocellulose from Brazil, Indonesia and Thailand had directed the exporters to disclose all the information which ought to have been provided in the NCV response. The Authority in the present case should direct the parties to file a response compliant with the trade notice 10/2018.

### **E.2. Submissions made by other interested parties**

25. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
  - a. Annexure I of Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 provides guidelines for disclosure of information in confidential and non-confidential version. The domestic industry in the present investigation comprises of two producers namely M/s. Jindal Stainless Limited and M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited. Annexure I of the Trade Notice provides a certain standard of disclosure with regard to certain specific parameters of the domestic industry.
  - b. The standard provided for the disclosure of the 'Non-Injurious Price' in Trade Notice No. 10/2018 is 'Aggregated actual data must be provided in actual figure range +/- 10%'. The same has not been complied with by the domestic industry.
  - c. In contravention to the Trade Notice No. 10/2018, the domestic industry has kept several key economic parameters as confidential in the petition. Without such information, interested parties are not able to fully undertake a meaningful examination of injury parameters of the applicant industry.

- d. In essence, the applicant industry has neither provided a good cause for the purpose of claiming confidentiality on certain parameters, nor made available the proper non-confidential version of the said parameters for a reasonable understanding of the substance of the petition and to appreciate the content of the petition, as required under Rule 7 of the Anti-Dumping Rules and Article 6.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement.
- e. The claim of confidentiality by applicant industry is excessive with respect to the following factors:
  - Information relating the individual production and sales of both the petitioners (in trends).
  - The information in Format L.
  - Sales realization in Format H.
- f. It is submitted that the Designated Authority must evaluate the claims for confidentiality of information and not designate information as confidential without a proper examination. The decision of the Hon'ble Supreme Court of India in *Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority* 2003 (158) E.L.T. 673 (S.C.) is relevant in this regard. On the issue of treatment of confidential information, the Hon'ble Supreme Court held that confidentiality is not to be granted automatically and should be based on thorough scrutiny.

### **E.3. Examination by the Authority**

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

- 27. Non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties through the public file as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018.
- 28. With regard to the confidentiality of information, the Authority notes that the information provided on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

## **F. Miscellaneous Issues**

### **F.1. Submissions made by the Domestic Industry**

29. No submission has been made by the domestic industry with regard to miscellaneous issues.

### **F.2. Submissions made by the other Interested Parties**

30. The following submissions have been made by other interested parties with regard to miscellaneous issues:

- a. The Authority has conducted many trade remedy investigations on different types of 'Flat Rolled Products of Stainless Steel' in the past 17 years.
- b. Jindal Stainless Limited has been the sole or one of the constituents of domestic industry in all of the trade remedy investigations. Thus, it is clear from a bare perusal of the long list of trade remedy measures that the domestic industry has enjoyed sufficient protection in the form of trade remedy measures on the import of different types of 'Flat Rolled Products of Stainless Steel', including Grade 304, for a very long time. There is no requirement for further protection to the domestic industry on the imports of 'Flat Rolled Products of Stainless Steel-304 Grade' specifically.
- c. Material injury caused to the domestic industry due to imports of different types of 'Flat Rolled Products of Stainless Steel' has already been remedied during 17 years of trade remedial measures. Moreover, analysis of information provided in the petition makes it clear that the domestic industry is not suffering from any 'continued' material injury. Absence of injury to the domestic industry is also evidenced by the fact that no sunset review was initiated by the Authority or no application was filed by the domestic industry requesting for initiation of sunset review when the anti-dumping duty on import of 'Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of ASTM grade 304' from the EU, Korea, South Africa, Chinese Taipei, USA expired on 24th November 2016. In August 2019, the Designated Authority has rejected the request for initiation of safeguard duty investigation on 'Steel products'.
- d. Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, 1975 states that any anti-dumping duty imposed shall 'cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition'. An exception to the rule has been carved out in the proviso to section 9A(5) allowing the Central Government to extend the duties beyond the five year period, if it is of the opinion that the 'cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury'.
- e. It is clear that the legislative intent was to limit the application of duty to a period of five years. The extension of such duty is only an exception and should be exercised with caution. For extension of duty, domestic industry should be put to strict test to satisfy the Authority that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in the event of revocation of the duties.

### F.3. Examination by the Authority

31. As regards the contention that domestic industry enjoyed trade remedial protection for last 17 years, it is noted that trade remedy measure on the subject goods from the subject countries was imposed since 2015 only. The Authority in the present review investigation is examining whether or not the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

## G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

### G.1 Normal Value

32. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
  - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **G.2 Submissions made by the Domestic industry**

33. The following are the submissions made by the domestic industry in respect of normal value:

- China PR should be treated as non-market economy and normal value should be determined in terms of para 7 of Annexure I to the Rules. The applicants have determined normal value on the basis of the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
- Prices prevailing as per the MEPS Stainless Steel Review publication which reports domestic steel pricing data for flat and long product has been considered for calculating the normal value for Korea. These prices have been considered as the price of the product type most commonly sold.
- No information is available with regard to normal value in Malaysia. The normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production in Malaysia, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits.
- For calculation of export price, petitioners have relied upon transaction wise import data procured from DGCI&S and adjustment have been made for, ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and non-refundable VAT (only for China).
- The dumping margin for imports from the subject countries continues to be positive. Thus, even though the volume of imports has declined, the same are entering the market at dumped prices.

#### **G.3 Submissions made by other interested parties**

34. The following submissions have been made by other interested parties with regards to determination of dumping margin:

- Bahru has not filed the exporter's questionnaire response since Bahru had zero exports of the subject goods to India during the POI. In any case, the Designated Authority, during the original investigation pertaining to the subject goods, had held that manufacture of Stainless Steel 304 Grade by the process followed by Bahru does not qualify it to be a "producer from Malaysia" of the subject goods and individual treatment cannot be granted to Bahru for determination of their dumping margin.

#### **G.4 Examination by the Authority**

35. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the producers/exporters from subject countries co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire response.

#### **Market Economy status for China PR**

36. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
- ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

37. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that no producer/exporter from China PR has participated in the present sunset review investigation. Accordingly, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules. The normal value and export price for all the producers/ exporters from the China PR have been determined as below.

#### **G. 4.1 Determination of Normal Value from China PR**

38. As none of the producers from China PR have filed the supplementary questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis".

39. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

#### **G.4.2 Determination of Export Price from China PR**

40. In the absence of co-operation by any producer from China PR, the Authority has determined the net export price based on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, non-refundable VAT, port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from China PR has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

#### **G.4.3 Determination of Normal Value from Korea RP**

41. None of the producers/exporters from Korea RP have participated in the present review investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

#### **G.4.4 Determination of Export Price from Korea RP**

42. In the absence of co-operation by any producer from Korea RP, the Authority has determined the net export price based on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from Korea RP has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

#### **G.4.5 Determination of Normal Value from Malaysia**

43. None of the producers/exporters from Malaysia has filed the questionnaire response in the form and manner prescribed. Bahru Stainless Sdn. Bhd., Malaysia has filed injury submissions only. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

#### **G.4.6 Determination of Export Price from Malaysia**

44. In the absence of co-operation by any producer from Malaysia, the Authority has determined the net export price based on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from Malaysia has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

#### **G.5 Dumping Margin**

45. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

**Dumping Margin Table**

S. No.	Country	Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin %	DM Range %
1.	China PR	Any	***	***	***	***	20-30
2.	Korea RP	Any	***	***	***	***	10-20
3.	Malaysia	Any	***	***	***	***	0-10

#### **H. ASSESSMENT OF INJURY, CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

46. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

47. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the

injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

48. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited and M/s. Jindal Stainless Limited. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicants have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, the cost and injury information of the Applicants, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), have been examined.

#### **H.1 Submissions made by the Domestic Industry**

49. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- a. Imports from subject countries have declined. However, these imports continue to be made at dumped prices. Imports from other countries have increased significantly at dumped and subsidised prices. Subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and are in fact even below the cost of sales of the domestic industry. Imports are thus likely to have significant suppressing and depressing effect on the domestic prices in the event of cessation of ADD. Production, sales and capacity utilisation of the domestic industry have increased over the injury period. However, performance of the domestic industry in terms of profits, cash profits, profit before interest & tax and return on investments have declined in the POI. The domestic industry thus once again is suffering injury. While this is largely because of shifting of dumping to other countries, it clearly establishes fragile situation of the domestic industry and likelihood of injury in the event of cessation of ADD.
- b. Imports have remained significant at dumped and injurious prices. Imports have further increased in the POI.
- c. Imports, without ADD, are undercutting the prices of the domestic industry.
- d. Performance of the Domestic Industry first improved and then deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow, and has reached negative levels once again in view of dumped and subsidized imports from other sources. Thus, the domestic industry is in a vulnerable position.
- e. The causal link has already been established in the original investigation. In the present review investigation, the Authority as per Article 11.3 of the WTO Agreement has to only examine whether revocation of anti-dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping and injury. Thus, there is no requirement for the Authority to examine or establish causal link between dumping and injury.
- f. Imports of product under consideration from other countries have increased significantly, and a separate anti-dumping and anti-subsidy investigation is being conducted by the Authority on such imports.
- g. The demand of the product under consideration has not declined. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
- h. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.
- i. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- j. Technology for production of the product has not undergone any change nor there are any likely changes in coming future. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- k. The applicants have made exports of the subject goods to the extent possible. However, information relating to domestic sales only has been taken into consideration for assessment of injury.

**H.2 Submissions made by other interested parties**

50. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:

- a. As per Rule 11 and Annexure II of the AD Rules, the determination of injury to the domestic industry involves positive evidence and objective examination of the dumped imports and consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. However, in the present investigation, the Petitioners have not been able to show that there is any dumping and consequent injury to the domestic industry.
- b. The Petitioners have not been able to provide any positive evidence to show that there is material injury or likelihood of injury in this case caused due to alleged dumped imports of the subject goods.
- c. The Authority must determine the following:
  - Significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.
  - Effect of dumped imports on prices of product under consideration in the domestic market and price suppression and depression.
  - Evaluation of decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity.
  - Actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
- d. It is submitted that the price undercutting is negative for the subject countries as per the Domestic Industry's own admission. As regards price suppression/depression, the Domestic Industry has itself stated in the petition that any price suppression/depression to the Domestic Industry is on account of the imports from other sources.
- e. There is no examination of injury margin or price underselling in the application. Therefore, it cannot be said that the imports of the subject goods are at injurious prices.
- f. The landed value of the subject goods from subject countries is above the landed value of the subject goods from other countries and the selling price of the Domestic Industry. Therefore, the exporters from the subject countries are matching the prevailing prices in India which is being set by the Domestic Industry and the exporters from non-subject countries.
- g. The Domestic Industry submitted that the imports are entering at prices that are having significant suppressing effect on domestic prices. This submission is contrary to the admission of the Domestic Industry in their petition wherein they have admitted that there is no price/suppression depression on account of the imports from subject countries. Further, this submission is also contrary to the facts on record as the selling price of the Domestic Industry is below the landed value of imports from the subject countries which indicates that the Domestic Industry in fact is suppressing the prices of imports from the subject countries.
- h. The Domestic Industry has submitted that the imports are happening at cheap prices on account of the FTA signed by India with subject countries. It is submitted that the said submission of the Domestic Industry makes it abundantly clear that injury, if any, to the Domestic Industry is on account of factors other than the dumping of subject goods.
- i. Any injury faced by the Domestic Industry is on account of the factors other than the alleged dumped imports. In fact, the petition of the Domestic Industry itself admits at different junctures that the injury caused to the Domestic Industry is on account of the high volume of imports from non-subject countries at low prices.
- j. While the imports from the subject countries have declined significantly during the entire injury investigation period, imports of the subject goods from non-subject countries increased significantly. Further, the import prices from non-subject countries as well as the selling price of the Domestic Industry are lower as compared to the prices from subject countries.

- k. Imports of subject goods from Malaysia do not get benefit of preferential customs duty at the time of importation into India. If customs duty has been collected on imports of subject goods from Malaysia, the Authority is requested to include 7.5% customs duty while calculating landed value of imports from Malaysia for determination of price undercutting and price underselling.
- l. Imports from Malaysia are less than 3% and cannot be cumulated with the imports from Korea RP and China PR. The Authority must conduct the injury assessment pertaining to alleged dumped imports from Korea RP and China PR separately from the assessment of injury due to alleged dumped imports from Malaysia.
- m. The imports from Malaysia accounted for 0.05%, 0.07%, 0.18% and 0.35% of the total imports into India in the years 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19, respectively.
- n. Overall, imports from subject countries declined in absolute volumes from 26,062 MT in 2015-16 to merely 2,387 MT during the POI, a decline to about a tenth of the original volumes.
- o. Even in relative terms, imports from subject countries declined in relation to total Indian production and total Indian consumption, from 100 indexed points in 2015-16 to merely 7 indexed points and 9 indexed points in the POI, respectively.
- p. It is critical to note that imports from Malaysia have always been low, throughout the POI and injury period. Even in the Original investigation, imports from Malaysia were at a very low level.
- q. It is evident that Malaysia has always been a marginal (almost de minimis) exporter to India in the last 10 years or so. Thus, there can be no claim that imports from Malaysia are causing injury to the domestic industry.
- r. Imports are not undercutting the prices in the POI and the price undercutting is negative.
- s. Domestic industry's assessment of price parameters is quite perfunctory and lacks an in-depth understanding of the price movement in the global and domestic markets, specifically with respect to the prices from the subject countries.
- t. It is submitted that the price undercutting from all three subject countries i.e. China PR, Korea RP and Malaysia is in the range of 0-(10), meaning that prices from subject sources were higher and did not undercut domestic prices. However, in order to twist the parameter in favour of the domestic industry, the domestic industry suggested the exclusion of certain transactions and derived price undercutting based on remaining transactions.
- u. With respect to transactions from Malaysia, the Petitioners have simply excluded all transactions pertaining to Hot-Rolled Flat Products Plate 304. Such an absolute exclusion of a category of products, for the sole reason that the pricing of the products is high shows that the domestic industry is attempting to make out a case for price undercutting where none exists.
- v. It is submitted that in assessing the price undercutting of the domestic prices by the prices of the subject goods from the subject countries, the Authority must compare the import prices after addition of anti-dumping duties. This is because the customers would compare the final prices payable by them while deciding their supplier and therefore, price undercutting should be seen at the level of import prices after addition of anti-dumping duties. This has also been the Authority's approach in several cases where price undercutting was considered after addition of ADD to the import prices, for the purposes of such assessment.
- w. It is submitted that once ADD is added to the landed value from Malaysia, it becomes evident that the price levels of the subject goods from Malaysia are significantly higher than the price levels of comparable subject goods from all other sources, and even comparable /higher than the NIP of the Petitioners
- x. The landed prices from Malaysia have increased over the period of injury and in the POI and are at their highest level during the POI.

- y. The price undercutting from Malaysia (presumably, without ADD) is negative, i.e, the landed price from Malaysia was higher than the NSR of the Domestic Industry.
- z. The landed price from subject countries as a whole has increased over the period of injury and in the POI and are at their highest level during the POI.
- aa. The price undercutting from subject countries as a whole (presumably, without ADD) is negative, i.e., the landed prices from the subject countries as a whole remained higher than the NSR of the Domestic Industry.
- bb. The domestic industry's net selling price has consistently increased over the period of injury and in the POI.
- cc. When there is no price undercutting in the present case, even without inclusion of ADD element in landed prices, then the prices of the subject imports are clearly significantly higher than the prices of the domestic. In such a case, there can be no question of imports from the subject countries exerting price pressure or causing price suppression or depression as is being argued in the present case. Thus, the imports are not entering India at suppressive or depressive prices.
- dd. Price underselling is not a parameter for assessing price effect of subject imports. The Hon'ble Gujarat High Court in *Nirma v. Union of India* has clarified this position.
- ee. The constructed NIP appears to be excessively inflated in order to derive an injury margin, regardless of the actual situation faced by the Petitioners.
- ff. For the purpose of injury margin / price underselling, the Authority considers the landed price with addition of ADD and compare the price so derived against the constructed NIP of the domestic industry.
- gg. The domestic industry has not increased their installed capacity for production of the subject goods.
- hh. The Petitioners' production of the subject goods has increased from 100 indexed points in 2015-16 to 124 indexed points in POI.
- ii. The Petitioners have improved their capacity utilization throughout the period of injury, from 100 indexed points in 2015-16 to 126 indexed points in POI.
- jj. The Petitioners have increased domestic sales of PUC commensurate to increased production of PUC over the period of injury.
- kk. The Petitioners' domestic sales have increased from 100 indexed points in 2015-16 to 125 indexed points in POI, following parallel with improvement in production of PUC.
- ll. The productivity of the Petitioners has shown improvement, from 100 indexed points per day to 127 indexed points per day over the period of injury. The increase in productivity per day indicates better production which must be seen in context of improved sales and lower inventories.
- mm. The inventory held by the petitioners has significantly declined, from 100 index points to 68 indexed points.
- nn. The inventory as no. of days of production and sales have moved in tandem to decline from 100 indexed points to almost half, 54 indexed points.
- oo. Since non-injurious price is to be computed at ex-factory level, post manufacturing expenses such as stockyard expense, advertisement and publicity, selling expenses, freight and forwarding expenses, provision for doubtful debts/advances, Bad Debts etc. shall not be considered while assessing non-injurious price.
- pp. It must be verified whether Research and Development expenses of Jindal Stainless Ltd. are related to PUC or not.
- qq. There are flaws in the data/information submitted by the domestic industry in its petition. PBIT per unit of domestic sales is negative i.e. (206) indexed points during POI, whereas,

total PBIT of domestic sales is positive which is 27 indexed points during the same period. PBIT as % of capital employed is also positive during the same period. It is submitted that how it is possible that when overall profitability of the domestic industry with respect to domestic sales is positive but per unit profitability of domestic sales is negative. It is submitted that there are flaws in the data of the domestic industry and it needs to be checked thoroughly by the Authority.

- rr. The Petitioners have noted a very high volume of imports from non-subject sources, without any express price comparison of such imports against the prices of either the domestic producers or subject imports. However, we note that the very high volumes of imports from non-subject sources – specifically Indonesia and Taiwan- appears to be causing injury to the Petitioners, if any
- ss. The volume of imports from Indonesia and Taiwan is significantly greater than the volume of imports from the subject countries. In fact, imports from Indonesia and Taiwan account for almost 90% of the non-subject imports.
- tt. While the imports from the subject countries show an overall declining trend, the imports from Indonesia and Taiwan have surged in the last two years to occupy a significantly larger share of total imports into India, together accounting for 85% of the imports into India.
- uu. Along with significant volumes of imports from Indonesia and Taiwan- the prices at which such imports are entering the Indian market is also significantly low, and comparatively much lower than prices from Malaysia.
- vv. There is a parallel investigation ongoing, qua the flat products of stainless steel from China PR, Taiwan, Indonesia, USA, Thailand, South Africa, Mexico, UAE, Singapore, Hong Kong, Vietnam and Malaysia. The Authority must assess the injury in that investigation, prior to proceeding in the present investigation to ensure that there is no situation of double remedies or that the subject countries are not unduly penalized for injury caused by non-subject countries.
- ww. The Petitioners' profitability and impact thereon is easily explained when viewed in the context of the imports from Indonesia and Taiwan.
- xx. The surge in imports from Indonesia and Taiwan coincides with the turn-around in the situation of the Domestic Industry- from booming profits to staggering losses in the years 2017-18 and 2018-19 (POI). Prior to this, there were relatively low import volumes from Taiwan and NIL import volumes from Indonesia.
- yy. The volume of imports from the subject countries and their prices on the one hand compared with the Petitioners' cost of sales, selling price and profitability on the other hand depict no trend or correlation. Rather, it projects a confusing picture wherein the Petitioners' prices are being slashed when the subject imports' prices are increasing.
- zz. The surging imports from Indonesia and Taiwan at low prices started entering India in 2017-18, coinciding absolutely with the decline in profitability parameters of the Petitioners. Concurrently, the volume and pricing of the subject goods from the subject countries can also be seen- the volumes are insignificant, and the prices are at comparable levels. With respect to Malaysia, the prices from Malaysia are significantly higher than prices from Indonesia and Taiwan during 2017-18 and POI.

### H.3 Examination by the Authority

- 51. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of

the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

52. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

53. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under:

*“(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*

54. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any. The Authority has taken note of the submissions made by domestic industry and other interested parties and has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

55. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

#### I. ASSESSMENT OF DEMAND

56. For this purpose, demand or apparent consumption of the product in India is taken as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. Share of imports from the subject countries in demand/consumption in India is as under:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<b><u>Imports Volume</u></b>					
China PR	MT	24,256	7,152	6,558	564
Trend	Indexed	100	29	27	2
Korea RP	MT	1,782	942	1,852	1,633
Trend	Indexed	100	53	104	92
Malaysia	MT	24	21	85	191

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Trend	Indexed	100	90	362	811
Total imports from subject countries	MT	26,062	8,115	8,495	2,387
Trend	Indexed	100	31	33	9
Other countries	MT	18,264	21,457	38,287	52,893
Trend	Indexed	100	117	210	290
Total imports	MT	44,326	29,573	46,782	55,280
Trend	Indexed	100	67	106	125
DI domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	106	125
Other Indian producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	104	101
Total demand	MT	152,001	135,234	160,745	187,337
Trend	Indexed	100	89	106	123
<b>Market share</b>					
Share of domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	100	101
Share of China PR	%	15.96%	5.28%	4.08%	0.30%
Trend	Indexed	100	33	26	2
Share of Korea RP	%	1.17%	0.70%	1.15%	0.87%
Trend	Indexed	100	59	98	74
Share of imports of Malaysia	%	0.02%	0.02%	0.05%	0.10%
Trend	Indexed	100	101	342	658
Share of imports of subject countries	%	17.15%	6.00%	5.28%	1.27%
Trend	Indexed	100	35	31	7
Share of imports of other countries	%	12%	16%	24%	28%
Trend	Indexed	100	132	198	235
Share of other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	98	82

57. It is noted that:

- Imports from China PR have reduced from 24,256 MT in 2015-16 to 564 MT during POI.
- Imports from Korea RP have reduced marginally from 1,782 MT in 2015-16 to 1,633 MT during POI.
- Imports from Malaysia throughout the POI and injury period have been extremely low as compared to other subject countries.

- d) Overall, imports from subject countries declined in absolute volumes from 26,062 MT in 2015-16 to 2,387 MT during the POI.
- e) Market share of imports from China PR, Korea RP and Malaysia during POI is 0.30%, 0.87% and 0.10% respectively.
- f) Market share of imports from other countries has increased from 12% in 2015-16 to 28% during POI.
- g) Demand has increased in POI as compared to the earlier years.

## II. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS

### i. Import Volumes and Share of Subject Countries

58. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject countries and other countries based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S. The import volumes of the subject goods and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<b><u>Imports Volume</u></b>					
China PR	MT	24,256	7,152	6,558	564
Trend	Indexed	100	29	27	2
Korea RP	MT	1,782	942	1,852	1,633
Trend	Indexed	100	53	104	92
Malaysia	MT	24	21	85	191
Trend	Indexed	100	90	362	811
Total imports from subject countries	MT	26,062	8,115	8,495	2,387
Trend	Indexed	100	31	33	9
Imports from other countries	MT	18,264	21,457	38,287	52,893
Trend	Indexed	100	117	210	290
Total imports	MT	44,326	29,573	46,782	55,280
Trend	Indexed	100	67	106	125
Imports from China PR in relation to total imports	%	54.72%	24.18%	14.02%	1.02%
Trend	Indexed	100	44	26	2
Imports from Korea RP in relation to total imports	%	4.02%	3.19%	3.96%	2.95%
Trend	Indexed	100	79	98	73
Imports from Malaysia in relation to total imports	%	0.05%	0.07%	0.18%	0.35%
Trend	Indexed	100	134	343	650
Subject countries import in relation to total imports	%	58.80%	27.44%	18.16%	4.32%

Trend	Indexed	100	47	31	7
Imports from China PR in relation to total Indian Production (HR 304)	%	16.73%	4.30%	3.79%	0.32%
Trend	Indexed	100	26	23	2
Imports from Korea RP in relation to total Indian Production (HR 304)	%	1.23%	0.57%	1.07%	0.92%
Trend	Indexed	100	46	87	75
Imports from Malaysia in relation to total Indian Production (HR 304)	%	0.02%	0.01%	0.05%	0.11%
Trend	Indexed	100	78	303	660
Subject countries import in relation to total Indian Production (HR 304)	%	17.97%	4.88%	4.90%	1.34%
Trend	Indexed	100	27	27	7
Demand	MT	152,001	135,234	160,745	187,337
Trend	Indexed	100	89	106	123
Share of imports from China PR in relation to Indian consumption/demand	%	15.96%	5.29%	4.08%	0.30%
Trend	Indexed	100	33	26	2
Share of imports from Korea RP in relation to Indian consumption/demand	%	1.17%	0.70%	1.15%	0.87%
Trend	Indexed	100	59	98	74
Share of imports of Malaysia in relation to Indian consumption/demand	%	0.02%	0.02%	0.05%	0.10%
Trend	Indexed	100	101	342	658
Share of imports of subject countries in relation to Indian consumption/demand	%	17.15%	6.00%	5.28%	1.27%
Trend	Indexed	100	35	31	7

59. It is noted that:

- Imports of subject goods from China PR have reduced in relation to production and consumption in India during the injury period and POI. During POI, share of imports from China PR in relation to total imports is 1.02%. Imports from China PR in relation to total Indian production and consumption has significantly declined from 100 indexed points in 2015-16 to 2 indexed points during POI.
- Imports of subject goods from Korea RP have reduced in relation to production and consumption in India during the injury period and POI. During POI, share of imports from Korea RP in relation to total imports is 2.95%. Imports from Korea RP in relation to total

Indian production has declined from 100 indexed points in 2015-16 to 75 indexed points during POI. Similarly, imports from Korea RP in relation to total consumption has declined from 100 indexed points in 2015-16 to 74 indexed points during POI.

c) Imports of subject goods from Malaysia have increased in relation to production and consumption in India during the injury period and POI. During POI, share of imports from Malaysia in relation to total imports is 0.35%. Imports from Malaysia in relation to total Indian production has increased from 100 indexed points in 2015-16 to 660 indexed points during POI. However, imports from Malaysia have always been minimal in absolute terms.

### III. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

60. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

#### i. Price Undercutting

61. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Particulars	UOM	China PR	Korea RP	Malaysia
Import volume	MT	564	1,633	191
Landed value	Rs./MT	158,393	151,664	158,747
Domestic selling price	Rs./MT	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	(***)	***	(***)
Price Undercutting	%	(***)	***	(***)
Price Undercutting	Range	(10)-0	0-10	(10)-0

62. It is noted that:

- a) Imports of the subject goods from Korea RP are undercutting the domestic selling price of the like article in India.
- b) Imports from China PR and Malaysia are not undercutting the domestic selling prices in the POI.

#### ii. Price Underselling

63. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the NIP determined in terms of Annexure III of the Rules has been compared with the landed price of imports as obtained from the DGCI&S import data. Comparison of the NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Particulars	UOM	China PR	Korea RP	Malaysia
Import volume	MT	564	1,633	191
Landed value	Rs./MT	158,393	151,664	158,747
NIP	Rs./MT	***	***	***

Injury margin	Rs./MT	***	***	***
Injury margin	%	***	***	***
Injury margin	Range	0-10	10-20	0-10

64. It is noted that the landed price of imports from the subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject countries.

### iii. Price Suppression and Depression

65. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices and landed value over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost to make and sell	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	112	123
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	110	118
Landed Value	Rs./MT	1,41,610	1,27,131	1,41,033	153,820
Trend	Indexed	100	90	100	109

66. Authority notes that cost of production for the domestic industry has increased from 100 indexed points in 2015-16 to 123 indexed points during POI, whereas, domestic selling price has increased from 100 indexed points in 2015-16 to 118 indexed points during POI.

#### H.4 Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

67. Annexure II to the Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

##### a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

68. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production (Total)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	128	126

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	121	124
Production (NPUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	129	127
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	128	126
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	106	125

69. From the above table, the following can be seen:

- Capacity throughout the injury investigation period and the period of investigation has remained constant.
- Production, capacity utilisation and domestic sales have increased over the injury period in view of increase in demand.

**b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit**

70. The cost of sales, selling price, profit/ loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	308	-29	-206
Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	301	-30	-256
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	60	27
Cash profit	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	172	37	-53
ROI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	173	88	36

71. It is seen that profits, return on investment and cash profits first increased during 2016-17 after levy of anti-dumping duty, but thereafter declined in 2017-18 and POI.

**c) Market Share in Demand**

72. The effect of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry has been examined as below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Share of domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	100	101
Share of China PR	%	15.96%	5.28%	4.08%	0.30%
Trend	Indexed	100	33	26	2

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Share of Korea RP	%	1.17%	0.70%	1.15%	0.87%
Trend	Indexed	100	59	98	74
Share of imports of Malaysia	%	0.02%	0.02%	0.05%	0.10%
Trend	Indexed	100	101	342	658
Share of imports of subject countries	%	17.15%	6.00%	5.28%	1.27%
Trend	Indexed	100	35	31	7
Imports from other countries	%	12%	16%	24%	28%
Trend	Indexed	100	132	198	235

73. The Authority notes that the market share of the domestic industry increased significantly during the year 2016-17 but has declined thereafter during 2017-18 and marginally improved in POI. However, share of imports from non-subject countries have increased significantly from 100 indexed points in 2015-16 to 235 indexed points during POI.

**d) Employment, Wages and Productivity**

74. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Employee	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	97	98
Wages	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	117	97
Productivity/Employee	MT/Employee	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	124	127
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	128	126

75. The Authority notes that employment and wages of the domestic industry has slightly declined in POI, whereas, productivity per employee has increased from 100 indexed points in 2015-16 to 127 indexed points during the POI.

**e) Inventory**

76. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Opening stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	155	57
Closing stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	41	76
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	89	68

77. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry has increased during 2016-17 and then decreased during 2017-18 and POI.

**f) Magnitude of Dumping**

78. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing or likely to cause injury to the domestic industry. It is noted that imports from the subject countries are entering into India at dumped prices and the margin of dumping are positive and above *de minimis* limits.

**g) Ability to raise capital investment**

79. The Authority notes that the profits of the domestic industry have declined as the volume of imports from other countries have increased. The domestic industry has earned a low return on its capital employed.

**h) Growth**

80. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Production (HR 304)	%		15%	4%	3%
Domestic sales	%		-2%	8%	18%
Domestic profit-Per MT	%		208%	-109%	-617%
Domestic profit-Per Lacs	%		201%	-110%	-742%
Cash profit	%		72%	-78%	-243%
PBIT	%		47%	-59%	-55%
ROI	%		7%	-9%	-5%

81. The Authority notes that volume parameters of the domestic industry like production and domestic sales have improved. However, price parameters of the domestic industry like profitability, return on investment have deteriorated during POI.

**i) Factors Affecting Domestic Prices**

82. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from China PR and Malaysia are above the selling price of the domestic industry and landed value of imports from Korea RP is below the selling price. The landed value from the subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry causing price underselling in the Indian market.

**Other Known Factors & Causal Link**

83. The Authority has noted other factors listed under the Rules, which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

**a) Volume and price of imports from third countries**

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
<u>Imports Volume</u>					
China PR	MT	24,256	7,152	6,558	564
Korea RP	MT	1,782	942	1,852	1,633

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Malaysia	MT	24	21	85	191
Subject Countries	MT	26,062	8,115	8,495	2,387
Other Countries	MT	18,264	21,457	38,287	52,893
Total	MT	44,326	29,573	46,782	55,280
<u>Imports Value</u>					
China PR	Rs./MT	130,354	115,942	126,838	147,342
Korea RP	Rs./MT	157,940	144,171	153,817	151,057
Malaysia	Rs./MT	128,748	122,889	150,337	158,747
Subject Countries	Rs./MT	132,238	119,238	132,955	150,795
Other Countries	Rs./MT	124,980	115,729	135,673	147,965

84. The Authority notes that volume of imports of subject goods has reduced from subject countries during the injury investigation period, which may be due to anti-dumping measures in force. The volume of imports coming into India from other countries (particularly from Taiwan and Indonesia) has witnessed increased.

**b) Export Performance**

85. The Authority notes that Applicants have made exports of the subject goods, however, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

**b) Technology**

86. The Authority notes that the technology for producing the PUC has not undergone any significant development. Possible development in technology is not a factor to cause injury to the domestic industry.

**c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

87. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

**d) Changes in pattern of consumption**

88. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

**e) Performance of the domestic industry with respect to other products**

89. Performance of other products being produced and sold by the Applicants is not a possible cause of injury to the domestic industry as the information on performance furnished by the Applicants relating to product under consideration only.

**I. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN**

90. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of utilities over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated

considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed price of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows:

**Injury Margin Table**

S.No.	Country	Producer	NIP- US\$/ MT	Landed Value US\$/ MT	Injury Margin US\$/ MT	Injury Margin %	Injury Margin Range- %
1.	China PR	Any	***	2237	***	***	0-10
2.	Korea RP	Any	***	2142	***	***	10-20
3.	Malaysia	Any	***	2242	***	***	0-10

**I.1 Conclusions on Injury:**

91. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that:

- There has been a decrease in the volume of dumped imports from subject countries during period of investigation.
- Imports from other countries have increased significantly.
- Dumping margin from the subject countries is positive.
- Imports continued to be made at dumped prices despite duties being in force.
- Subject imports are causing price underselling effect on the prices of the domestic industry.
- Performance of the Domestic Industry in terms of profits, return on investments, cash flow has deteriorated in 2017-18 and the POI.

**J. CONCLUSION ON LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

**J.1 Submissions made by the domestic industry**

92. The following submissions have been made by domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- There is a clear likelihood of the continued dumping being further intensified by exporters from China PR leading to a situation of further intensified injury to the domestic industry, if the existing duty is withdrawn.
- Though the volume of subject imports has declined post imposition of anti-dumping duty but the prices at which imports are coming are dumped and injurious prices. Thus, cessation of duties is likely to lead to intensified dumping and consequent injury to the domestic industry. The dumping margin is positive and the domestic industry is currently suffering injury.
- The imports of the subject goods declined over the injury period, however, post POI imports have shown increase with further decline in the import price.

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post POI (H1 Annualised)
Imports volume	MT	26,062	8,115	8,495	2,387	10,384
Imports Price	Rs/MT	132,235	119,236	132,961	150,817	139,503

It may be seen that imports have increased by 31% in the post POI period since the POI and import prices have declined by 9% for the same period. Such increase in imports, coupled with decline in import prices goes on to establish that in the event of cessation of the present anti-dumping duty, the imports will further increase significantly causing further injury to the domestic industry.

- d. The global market scenario for the product under consideration witnessed significant change in 2010 when suddenly the supply of the product under consideration far exceeded the demand. The demand supply gap has since then increased globally. This shift has been triggered by China which has become a net exporter from being a net importer by establishing mammoth capacities far exceeding the demand. China is the largest exporter and producer of subject goods. Further, China, with its belt and road initiatives and going out policies, is expanding its reach through other countries. China and Korea, both have surplus capacities. Freely disposable capacities have been determined by deducting apparent consumption from the existing capacities of Slab in these countries as per the information published in CRU International “Stainless Steel Flat Products Market Outlook February 2020 Statistical Review”.
- e. It is relevant to note that the basic production process involved in the production of the product under consideration involves melting the inputs such as scrap/ore and ferro-alloys. The output of steel making furnace is a slab. Slab is a semi-finished steel product with a rectangular cross section and is used as a starting material in the production process of stainless steel hot-rolled flat products, i.e. hot-rolled sheets and strips. The hot rolling process begins at the reheat furnace where the slabs are heated to 1100- 1300°C, depending on the stainless-steel grade. The hot rolled products are softened (annealed) and descaled (pickled with acids). Cold rolling of the Hot rolled stainless steel takes place in cold rolling mills by rolling the HR steel. Cold rolled products cannot be made directly from scrap or slab.
- f. In view of significant surplus capacities available with producers in subject countries, it is likely that in the event of cessation of present duty imports will increase manifold.
- g. The producers in the subject countries are massively export oriented units. Export of HR Coil and HR Plate from the subject countries is shown in the table below:

Period	China PR	Malaysia	Korea RP
2014	16,78,561	21,679	7,66,934
2015	15,11,377	20,611	7,63,471
2016	18,31,883	30,633	7,80,221
2017	18,64,440	35,212	7,61,271
2018	16,25,769	38,177	8,30,894
2019	12,38,362	48,885	8,33,309
2020	12,22,010	38,436	7,51,932

Unit: KT

- h. It may be seen that Malaysia has been exporting HR products (coils and plates). The major producer in Malaysia, Acerinox and Bahru Stainless, have related parties in other countries who export goods to various countries. The volume of exports from the subject countries is substantial.
- i. The level of trade distortion in stainless steel globally can be gauged from the number of trade remedial measures imposed or ongoing. A number of countries have imposed trade defence measures on China, Korea and Malaysia (the subject countries). Various measures imposed on the subject countries restrict the market available to them. India being a favourable market, the producers are likely to intensify exports at dumped prices in the event of cessation of anti-dumping duties. Thus, surplus capacities coupled with the fact of

restricted market for the producers with excess capacity indicates that the exports to India will increase as India is an attractive destination with significant demand.

- j. The product has a long history of continued and renewed dumping in the Country. Imposition of antidumping duties have led to decline in imports from subject countries, however imports have intensified significantly from other countries at significantly low price. Globally, producers are faced with significant surpluses and have resorted to dumping the product. The producers are waiting for an opportunity to divert exports to price attractive destinations. As stated earlier, the investigation initiated on stainless steel flat products excludes the present subject goods. Thus, in the event of duties getting imposed on stainless steel flat products and at the same time withdrawal of the present duties from the subject goods will imply that intensified dumping shifting back to the subject countries.
- k. India is the second largest producer & consumer of stainless steel. Further, India was also the only market where stainless-steel consumption was growing at a CAGR of 9-10% per annum. The World Steel Association (worldsteel) in its Short Range Outlook (SRO), stated that demand for stainless steel is expected to decline in the coming future, all over the world. Demand of steel is also expected to come down in China and Korea. With the current global pandemic, the consumption of stainless steel and subject goods have declined not just in India but globally. This is making the Indian market lucrative for exporters struggling with excess capacities.
- l. Decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty. The US policy on conducting sunset review investigations has been referred in this regard. Consistent approach followed by investigating authorities around the world is that in case of decline in imports or low imports, there is a need to investigate whether there is likelihood of recurrence of dumping and injury, in the event of cessation of duties. This proposition is supported by the findings and decisions of the investigating authorities in other jurisdictions including India in the past.
- m. Landed value of imports are at a price much lower than the selling price and cost of sales of the Domestic Industry. Imports are entering at prices that are having a significant suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports. It is likely that the producers in subject countries shall further aggressively target and take over the entire Indian demand in a nearly foreseeable future.

## J.2 Submissions made by other interested parties

93. The following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. The domestic industry has relied on the capacities in Taiwan for computation of freely disposable capacities in the subject countries. The said approach adopted by the Domestic Industry is not permissible in law and is contrary to the other investigation being carried out by the Authority in past, as well as the ongoing AD investigation filed by the Domestic Industry itself against imports of flat products of stainless steel (F. No. 6/12/2019-DGTR) wherein China and Taiwan have been taken as separate subject countries.
- b. Para vii(b) of Annexure II requires a further analysis of availability of other export markets to absorb any additional exports. However, there is no such examination in the application of the Domestic Industry. It is submitted that the Authority has time and again stated that merely presence of freely disposable capacities in the subject countries is not sufficient but the Domestic Industry is required to establish that the said freely disposable capacity shall be diverted into India in the event the duties are revoked and there is no other exports market that may absorb any additional exports. Therefore, the Domestic Industry fails to satisfy this condition as well.
- c. The Domestic Industry has relied upon the data of steel as a whole to indicate freely disposable capacities in the subject countries. It is submitted that such a broad data of steel in

general cannot be accepted for reaching any conclusion with respect to the Product under Consideration.

- d. However, the whole analysis of the Domestic Industry concerning the likelihood analysis pertains to the data of steel in general and not the Product under Consideration. The respondents submit that the said data of steel in general cannot be relied upon to come to any conclusion with respect to the specific Product under Consideration in the present case.
- e. The Domestic Industry has provided the inventories of steel in general in Korea RP. While there is no analysis at all with respect to inventories in other two subject countries i.e., China PR and Malaysia, the information relating to Korea RP also cannot be accepted.
- f. The Authority would appreciate that unlike India, the anti-dumping duties in USA are prospective in nature which means that an exporter whose dumping margin is positive and on whose goods anti-dumping duties have been imposed can still claim refund of duties in next annual review of the case if the dumping margin during the period of such review was negative or less than the dumping margin originally determined for the said exporter. On the contrary, the anti-dumping duty investigation in India are retrospective in nature. Therefore, practice in USA cannot be relied upon for reaching to any conclusion with respect to the likelihood of dumping or injury as India follows distinctly different procedure for determination and collection of anti-dumping duties.
- g. The capacities in Malaysia have significantly declined in the recent years and remains quite low, particularly in comparison with other countries. The Authority must note the declining trend of capacities in Malaysia, its consistently low exports to India and its significantly high prices, and the holistic reading of these elements establishes that Malaysia does not have “excess capacity”.
- h. The Petitioners have cited the World Steel Association Short Range Outlook (Annexure 4.3 of Petition at page 138) to claim that there is an expectation of decreasing demand for stainless steel, all over the world. However, it is submitted that the cited report explicitly states that “steel demand growth is expected to improve in 2020, dependent on a reduction in trade tensions”. As such, even by the Petitioners’ own data, it appears that the claim is unfounded and meritless. It is important to note that the report is quiet about the demand in Malaysia. As such, it appears that the Malaysian production and capacity is insufficient for factoring in global outlooks, and therefore is insufficient to cause any meaningful impact on the Petitioners.
- i. The Petitioners have provided a list of current measures imposed against stainless steel flat products. In this regard, it is noted that the entire list pertains to measures in force against almost any country and is not specific to the subject countries. In any case, the entire list mentions only one investigation against Malaysia, i.e., conducted by Vietnam. The measure was set to expire on 6 October 2019.
- j. The Petitioner’s claim regarding the alleged “shifting” of sources of dumping is based entirely on the duties imposed by the Authority in India. In this regard, we submit that imposition of duties does not reflect any “shifting of dumping from one source to another”. Rather, the existence of so many past duties shows that the product is a sensitive one and has been subject to investigation and duties, specific to those instances.
- k. With respect to Malaysia, the Petitioners cannot claim that either there has been high volume of imports or that the imports have affected the pricing of the Petitioners. The Malaysian imports have been historically low and must be recognised so.
- l. The Petitioner’s claim regarding India’s price attractiveness is based entirely on data treated as confidential. We submit that the selling price and the cost of sales of the Petitioners merits examination.
- m. The Petitioners have claimed that due to unforeseen circumstances arising out of the India-ASEAN FTA, there has been increase in imports from Malaysia. It is submitted that such a claim cannot be raised in view of the historically low volume of imports from Malaysia, even after the signing of the Indian-ASEAN FTA.

n. It is not appropriate to consider that Malaysia which accounted for 3.59% of total imports even in the original POI and currently holds 0.35% share of total imports is causing injury to the Domestic Industry.

### J.3 Examination by the Authority

94. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

95. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties earlier imposed on the imports of subject goods from subject countries. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, factors which may be taken into consideration viz.:

- a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- d) Inventories of the article being investigated.

96. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

(i) **Post POI imports of PUC**

97. For examining the Post-POI period imports into India, the Authority has obtained import data from DGCI&S and from that it is observed that imports during Post-POI have increased from subject countries when compared to POI. Post POI import data is as under:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post POI (April-September 2019)
China PR	MT	24,256	7,152	6,558	564	1,326
Korea RP	MT	1,782	942	1,852	1,633	3,803
Malaysia	MT	24	21	85	191	63
Total imports from subject countries	MT	26,062	8,115	8,495	2,387	5,192

98. It is noted that despite imposition of anti-dumping duties on imports of subject goods from subject countries, imports from China PR and Korea RP are coming in significant quantities.

(ii) **Surplus capacity with the exporters**

99. The domestic industry has provided freely disposable capacities of the subject goods in China PR and Korea RP which have been determined after deducting consumption from the existing capacities information provided in CRU International “Stainless Steel Flat Products Market

Outlook February 2020 Statistical Review". Based on the evidence available on record, the Authority notes that freely disposable capacities of subject goods available in China PR and Korea RP can be utilised for exports to India.

(iii) **Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports**

100. The Authority notes that volume of imports of subject goods has reduced from subject countries during the injury investigation period and the POI. However, the import volume has witnessed significant jump in the post POI. The domestic prices have been suppressed due to such imports.

(iv) **Inventories**

101. With regard to inventories, Domestic Industry has provided evidence with regard to inventories in Korea RP. The Authority notes that inventories available in Korea RP can be utilized to increase their exports to India.

102. In view of the above, the Authority notes the following:

- i. Imports from China PR have reduced from 24,256 MT in 2015-16 to 564 MT during POI. Imports from Korea RP have reduced marginally from 1,782 MT in 2015-16 to 1,633 MT during POI. Imports from Malaysia throughout the POI and injury period have been low including post POI period.
- ii. Imports from subject countries declined in absolute volume and in relation to total production and demand in India during injury investigation period and the POI. However, imports from China PR and Korea RP have increased during the post POI period.
- iii. Imports from subject countries are still coming at dumped prices.
- iv. Imports of the subject goods from Korea RP are undercutting the domestic selling price of the like article in India.
- v. Imports from China PR and Malaysia are not undercutting the domestic prices in the POI.
- vi. Volume parameters of the domestic industry like production and domestic sales have improved. However, price parameters of the domestic industry like profitability, return on investment have deteriorated during POI.

## POST DISCLOSURE COMMENTS

### K.1. Submissions by the Domestic Industry

103. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- a) M/s Bahru Stainless SDN. BHD., Malaysia is not an interested party in the present investigation under Rule 2(c) of the AD Rules as it is not an exporter, producer or trader of subject goods. CESTAT in M/s. Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority has held that a party cannot simply represent before the Designated Authority without establishing its status in an investigation.
- b) If the company claims that it has not exported the product to India, the company ceases to be an interested party. If the company claims to be an interested party as a foreign producer, then, the company was obliged to file questionnaire response, irrespective of whether the company has exported the product to India. The company was required to show their third countries exports.
- c) Prices from Malaysia have declined post POI. Imports, even at low volume, continue to be made at dumped and injurious price. Thus, in the event of cessation of duty, imports are likely to intensify at dumped and injurious price causing injury to the domestic industry.
- d) Considering the slab capacity, the producers in China PR and Korea RP have significant surplus capacity. The basic production process involved in the production of the product under consideration involves melting the inputs such as scrap/ore and ferro-alloys. The output of steel making furnace is a slab which is an appropriate benchmark to examine excess capacity.
- e) A number of countries in the world have surplus capacity for stainless steel product and that is the reason various trade remedial measures are in force or ongoing against many countries. Thus, various countries have blocked their market for dumped imports.

- f) Significant exports are being made by China PR and Korea RP at price much below the price prevailing in India, thus making India a more price attractive country to export. The producers will look for market where they can attain better prices. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to lead to influx of dumped imports from these countries.
- g) Insignificant import volume cannot be a reason for not extending the anti-dumping duty in a sunset review investigation and the same was confirmed by the CESTAT in the matter of AIA Engineering vs Union of India.
- h) Non extension of present duty will also dilute the impact of parallel investigation which considers the imports of stainless-steel flat products from even the present subject countries and such investigation specifically excludes HR 304 from the product scope.
- i) Present duties need to be extended and modification in the quantum is not warranted in the present circumstances for another period of five years.
- j) Applicants request disclosure of communication sent to other parties, submissions received from other parties, Normal value determined on the basis of cost of domestic industry and Non injurious price in order to come to a meaningful conclusion.
- k) In the present situation of world pandemic, which has led to declining demand all over the world, various countries will be desperate to export in whichever way possible. Further, there have been several DRI cases on Bahru which shows that exporter has a history of engaging into malpractices and evade duties also.
- l) India is the second largest consumer of stainless-steel flat products which includes a significant part of hot rolled stainless steel flat products of 304 series. Demand for the subject goods has also declined due to the ongoing pandemic. Even assuming that the growth in demand in India has also gone down, considering the significant level of demand in India, it is likely that the Indian market will attract exports from these subject countries which have huge surplus and are highly export oriented.

## K.2. Submissions by other interested parties

104. The submissions made by other interested parties are as follows:

- a) The Authority has not considered the following submissions:
  - Submissions relating to the data relied by the Domestic Industry not pertaining to Product under Consideration.
  - Incorrect assessment of freely disposable capacities in the subject countries by the Domestic Industry as the data relating to such factor included Taiwan as subject country.
  - Absence of any analysis pertaining to availability of other export markets to absorb any additional exports in terms of para vii(b) of Annexure II.
  - Submission regarding absence of price suppression/depression.
  - Submission regarding any injury to the Domestic Industry on account of other factors.
- b) The Designated Authority failed to appreciate that the applicants have not followed the direction with respect to confidentiality issued by the Authority vide Trade Notice No. 10/2018.
- c) The disclosure statement mentions that the Authority has analysed the import data of post-POI period (Apr – Sep 2019) for likelihood analysis. It is submitted that post-POI data itself has been taken for a period arbitrarily chosen to achieve pre-determined outcome. It is further submitted that no such data has been provided to the interested parties. In terms of Rule 7, any document that has been relied upon by the Authority is required to be provided to the interested parties in a non-confidential version. It is submitted that as per Rule 7, unless a non-confidential version of such document is provided to the interested parties, the Authority cannot rely upon such documents in its decision-making process.

- d) While the Authority has carried out the volume analysis of the imports from the subject countries in post-POI period, there is no price analysis for the same. It is submitted that any conclusion drawn on the basis of the post-POI data has to be on the basis of both volume and price analysis. Further, increased volume in post-POI period does not assume any significance in the absence of a corresponding price analysis.
- e) The examination of the Authority with respect to likelihood analysis is contrary to the legal requirements as well as the facts of the case for the following reasons:
  - It is submitted that para (vii) of Annexure II requires an examination relating to rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation. However, no such examination has been carried out by the Authority in the disclosure statement.
  - The Authority has relied upon the data of steel as a whole to indicate surplus capacities with the exporters and inventories of the Product under Consideration in the subject countries. It is submitted that such a broad data of steel in general cannot be accepted for reaching any conclusion with respect to the Product under Consideration. It is a matter of record that the Product under Consideration in the present case is a subset of overall steel production. In such a scenario, the Authority could not have relied upon the data of steel in general to advance arguments concerning the subject goods. In this regard, the Respondent relies on paras 7.111 and 7.112 of WTO panel report on *India- Certain Measures on Imports of Iron and Steel (DS518)*.
- f) The Authority in Section IV has provided the methodology for determining Non-Injurious Price, which will be used for determining injury margin. In this context, it is submitted that from a plain reading of the Section IV, it is observed that the Authority has simply mentioned the principles outlined in Annexure III to the Rules. However, there is no information in Section IV of the disclosure statement as to how actually the Authority has computed raw material cost, cost of utility, capacity utilization for normation of the cost.
- g) It is submitted that Malaysia's imports are insignificant during the injury investigation period and POI. In fact, imports from Malaysia have reduced even further in the post-POI period. Even if import trends from Malaysia are assessed from the period 2009-10, it is evident that imports from Malaysia have always been negligible into India. Thus, injury suffered by the domestic industry, if any, is not at all attributable to the imports from Malaysia.
- h) Authority has ignored submissions with regard to determination of non-injurious price. Authority needs to clarify whether post manufacturing expenses such as stock yard expense, advertisement and publicity, selling expenses, freight and forwarding expenses, provision for doubtful debts/advances, bad debts etc. have been considered while assessing non-injurious price or not.

### K.3. Examination by the Authority

105. Post- disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
106. With regard to the non-cognizance of some of the comments and submissions made by interested parties, it is noted that the Authority has as a matter of consistent practice and in terms of the legal requirement duly taken cognizance of all the submissions which it considered relevant for its analysis and decision making in the investigation.
107. The Authority has examined the post POI import data to assess likely behaviour of the exporting countries in so far as their exports to India are concerned.

108. With regard the requests that non-confidential versions of communications sent by the Authority and copy of the non-confidential version of replies filed by interested parties be made available, it is noted that all non-confidential versions of the submissions were made available in the public file before the nation-wide lockdown due to COVID-19. Thereafter, all non-confidential versions of communication which, as per DGTR's practice would have been put in the public file, have been shared through email with interested parties.

109. With regard the submissions concerning low volume of imports from subject countries, it is noted that the imports from subject countries have reduced after the imposition of anti-dumping duty. However, the imports still continue to come into India at dumped and injurious prices. It is also noted that imports from non-subject countries have increased significantly during the injury investigation period and a parallel anti-dumping investigation on stainless steel flat rolled products is being conducted against the non-subject countries. In such a scenario there is a likelihood that dumped imports from subject countries will increase if the existing anti-dumping duty is revoked.

110. With regard the submission that Bahru should not be considered as interested party under Rule 2 (c) of the Rules, it is noted that Bahru has made no exports of subject goods to India during POI. However, Bahru has made exports of subject goods to India in the past. The Authority further notes that filing of questionnaire response is not the criterion to become an interested party under Rule 2 (c) of the Rules. Thus, for the purposes of present review investigation, Authority has considered Bahru as an interested party and taken cognizance of the submissions made by Bahru.

111. With regard the submissions of interested parties concerning methodology adopted for non-injurious price (NIP) calculations, it may be noted that detailed guidelines for computation of NIP are laid down under Annexure III of the Rules and the same have been adopted while determining NIP in the present review investigation.

#### **L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST**

112. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

113. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

#### **M. CONCLUSION**

114. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- There is continued dumping of the subject goods from subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of revocation of duties.
- The domestic industry's performance in terms of volume parameters like production, sales etc. has improved but price parameters of the domestic industry like profitability, return on investment have deteriorated during POI.

- c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
- d. There is sufficient evidence to indicate that the cessation of anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry.

## N. **RECOMMENDATIONS**

115. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
116. Having concluded that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the imports of PUC from the subject countries.
117. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(i) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at column 3 of the duty table below, originating in or exported from subject countries.

**DUTY TABLE**

S No	Heading/Sub Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7219, 7220	Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel -304 series***	China PR	Any country including China PR	Any	160	US\$	MT
2	-do-	Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel -304 series***	Any country other than China PR, Korea RP and Malaysia	China PR	Any	160	US\$	MT
3	-do-	Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series***	Korea RP	Any country including Korea RP	Any	255	US\$	MT
4	-do-	Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series***	Any country other than China PR, Korea RP and Malaysia	Korea RP	Any	255	US\$	MT

5	-do-	Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series***	Malaysia	Any country including Malaysia	Any	155	US\$	MT
6	-do-	Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series***	Any country other than China PR, Korea RP and Malaysia	Malaysia	Any	155	US\$	MT

**Note -** Customs classification is only indicative and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to anti-dumping duty even when it is imported under any other HS code.

**\*\*\*Note-** Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel 304 series means “Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled annealed and pickled or black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or black finish; whether or not of quality prime or non-prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650mm (width tolerance of + 20mm for mill edge and + 5mm for trim edge)”.

#### O. FURTHER PROCEDURE

118. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority